PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 305 ● भिलाई, बुधवार 17 जून 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

संक्षिप्त समाचार

तमिलनाडु में 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, बिस्किट का लालच देकर किया रेप, गिरफ्तार

तिरुवल्लुर। तमिलनाडु में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की हैरान करने वाली खबर सामने आई है. तिरुवल्लुर जिले में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की शिकार हुई 3 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई. जिससे पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया है. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर चिंता फिर से गहरा गई है. पुलिस ने बताया पीड़िता बिहार की है. उसका परिवार तिरुवल्लुर जिले के गुम्मिडीपोंडी में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में रह रहा है. रविवार को झाड़ियों में बच्ची गंभीर हालत में मिली थी. उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सोमवार को उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने इस मामले में बिहार के एक प्रवासी मजदूर को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी बच्ची को जानता था और उसने बिस्कुट का लालच देकर उसे अपने साथ ले जाकर यौन उत्पीड़न किया. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने से कहा, बच्ची उसे जानती थी. उसने बिस्कुट देने का लालच दिया, उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की.अधिकारी ने इस मामले में एक से अधिक लोगों की संलिप्तता की आशंका को खारिज करते हुए कहा, यह सामूहिक बलात्कार का मामला नहीं है.

9000 किमी लंबे स्टेट हाईवे का होगा थीडी सर्वे, नेटवर्क सर्वे व्हीकल से होगी निगरानी

ग्वालियर। मप्र रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन प्रदेश में मौजूद अपने 15 हजार किमी लंबे रोड नेटवर्क को और बेहतर करने की कवायद कर रहा है। स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड (एमडीआर) के साथ ही पुलों के विकास, बेहतर रखरखाव के साथ ही ट्रैफिक संचालन को सुगम बनाने के लिए नौ हजार किमी लंबी सड़कों का थ्रीडी सर्वे कराने की तैयारी की गई है। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से छठे चरण के अंतर्गत सड़कों की बेहतरी के लिए मिली राशि का उपयोग किया जाएगा। इस सर्वे के अंतर्गत स्टेट हाईवे पर ट्रैफिक लोड, सड़कों की स्थिति का डेटा जुटाया जाएगा। इसके लिए कंसल्टेंट कंपनी को अधिकृत किया जाएगा, जो थ्रीडी कैमरों से लैस नेटवर्क सर्वे व्हीकल के माध्यम से सड़कों की थ्रीडी रिकार्डिंग करेंगी। अभी तक इस प्रकार का सर्वे गूगल जैसी कंपनियां अपने मैप फीचर को अपडेट करने के लिए समय-समय पर करती हैं

ऑपरेशन पुश बैक पर बीएसएफ-बीजीबी में बढ़ी तनातनी

नई दिल्ली। भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक बार फिर से बीएसएफ-बीजीबी में तनातनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. दोनों देशों की सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है. रानीनगर बॉर्डर पर 12 बांग्लादेशी नागरिकों की कथित घुसपैठ की कोशिश को लेकर भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक बार फिर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है.

पीएम मोदी को स्लोवाकिया ने दिया देश का सबसे बड़ा सम्मान

ऑर्डर ऑफद व्हाइट.....डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा

नई दिल्ली/ एजेंसी

पीएम मोदी को स्लोवाकिया ने अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफद व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया है. यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच संबंध मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया हो. यह किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 33वां वैश्विक सम्मान है. स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने पीएम मोदी को इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है 'द ऑर्डर ऑफ़द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)' स्लोवाकिया द्वारा विशेष रूप से विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक और सैन्य राजकीय सम्मान है. स्लोवाकिया द्वारा दिया गया यह सम्मान दोनों देशों के मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों पर मुहर लगाता है. क्रू मोदी को अब तक दुनिया के अलग-अलग देशों से मिले वैश्विक सम्मानों की कुल संख्या 33 हो गई है. पीएम मोदी ने इस सम्मान को लेते हुए कहा, 'यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों का है. मैं यह पुरस्कार भारत और स्लोवाकिया की अटूट दोस्ती को समर्पित करता हूं.'भारत और स्लोवाकिया ने सोमवार को प्रवासन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिफेंस जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक?स' पर लिखा, सोमवार को राष्ट्रपति पेलेग्रिनी के साथ हुई बातचीत में विनिर्माण, परिवहन, नवाचार और निवेश संबंधों, ऊर्जा, जैव ईंधन आदि जैसे विविध विषयों पर चर्चा हुई. स्लोवाकिया के बाद वह फ्रांस में होने वाली ज-7 समिट में शामिल होंगे, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी. पीएम मोदी और पीएम फिको, भारत-यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमत हुए. दोनों नेताओं ने सीमा-पार आतंकवाद और पहलगाम में हुए आतंकी हमले सहित हर तरह के आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की. यह सम्मान मिलने के बाद अब तक दुनिया के अलग-अलग देशों ने पीएम मोदी को कुल 33 बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिए हैं. यानी स्लोवाकिया का यह सम्मान उनका 33वां वैश्विक सम्मान बन गया है. इस वक्त भारत और स्लोवाकिया के बीच रिश्तों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है. दोनों देश मिलकर काम करना चाहते हैं और आपसी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं. ऐसे में यह सम्मान देना एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे यह भी साफहोता है कि स्लोवाकिया भारत के साथ अपने संबंधों को कितनी अहमियत देता है. पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों ने पीएम मोदी को अपने बड़े और सर्वोच्च सम्मान दिए हैं. अब स्लोवाकिया भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है. यह बात यह दिखाती है कि दुनिया के मंच पर भारत की पहचान और ताकत लगातार बढ़ रही है. पीएम मोदी को मिलने वाले ये सम्मान सिर्फ उनकी निजी उपलब्धि नहीं हैं, बल्कि ये इस बात का भी संकेत हैं कि दुनिया के देश भारत को एक बड़ी और जिम्मेदार ताकत के रूप में देख रहे हैं.

सोना-चांदी से बनता है स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान

स्लोवाकिया का यह सम्मान देखने में बेहद खूबसूरत लगता है, साथ ही इसे बनाने के लिए कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है. यह सम्मान सोने और चांदी दोनों को मिलाकर बनता है. पदक की चमक और मजबूती के लिए इसे सोने के साथ-साथ चांदी से भी बारीकी से जोड़ा जाता है. यही वजह है कि इन धातुओं से बना यह सिर्फएक सम्मान नहीं बल्कि स्लोवाकिया की कला और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक माना जाता है. अब मेडल में लगने वाले सोने की बात करते हैं तो रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें हाई क्वालिटी के 14 कैरेट या 18 कैरेट सॉलिड गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है. इसके स्टार और बैज दोनों को पूरी तरीके से ठोस सोने में ही ढाला जाता है. मेडल के ठीक बीचो-बीच में सफेद रंग के डबल क्रॉस को घेरने वाला पत्तियां भी शुद्ध सोने से तैयार होती हैं. पुरस्कार की अलग-अलग श्रेणियां होती हैं, जिसके अनुसार इसे तैयार करने में एक से तीन ट्राय औंस तक शुद्ध सोना लगाया जाता है.

राजनाथ सिंह के आवास पर जुटे बीजेपी के दिग्गज

2027 के लिए 7 राज्यों का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया....

नई दिल्ली। भाजपा की केंद्रीय टीम में पुनर्गठन की चर्चाओं के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई प्रमुख नेता भी शामिल हुए. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेताओं के बीच लगभग 4 घंटे तक एक उच्च स्तरीय बैठक हुई. पार्टी की नई केंद्रीय टीम के गठन को लेकर चर्चा हुई. भाजपा की केंद्रीय टीम में फेरबदल की अटकलों के बीच सोमवार को पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई. इस बैठक में कई दिग्गज नेता ने भी इंट्री ली. बैठक में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, अमित शाह, जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष, आरएसएस के अरुण कुमार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल हुए. देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और आने वाले चुनावों की तैयारियों पर करीब 4 घंटे तक चर्चा की गई. पार्टी की ओर से इस बैठक में की गयी बातों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया. लेकिन जानकारी के अनुसार बैठक में पार्टी की केंद्रीय टीम में संभावित फेरबदल समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. नितिन नवीन के नेतृत्व में नई केंद्रीय टीम की घोषणा इस महीने होने की संभावना है, जिसमें वरिष्ठ और युवा नेताओं का संतुलन देखने को मिल सकता है.

बिहार-बंगाल में भाजपा की जीत से बढ़ी अखिलेश की बेचैनी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में राजद और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार तथा भाजपा की ऐतिहासिक जीत ने उनके माथे की शिकन बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख इतने निराश और हताश हो चुके हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का भविष्य धूमिल नजर आने लगा है, जिसके चलते वे अवसाद में गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी कर धमकी की राजनीति पर उतर आए हैं।

163 बीघा जमीन से मिट्टी बेचा

अभिषेक बनर्जी सहित 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा विवाद सामने आया है. डायमंड हार्बर के भाजपा नेता अभिजीत विश्वास उर्फ बॉबी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी, उनके सहयोगी सहित कुल 23 लोगों के खिलाफ कथित रूप से अवैध मिट्टी कटाई और बिक्री के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है. सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ करीब 300 करोड़ रुपये के अवैध मिट्टी खनन और तस्करी के आरोप में एफआईआर दर्ज करायी गयी है. इस संबंध में सोमवार रात कालीतला-आशुलिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया है कि वर्षों से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से मिट्टी काटकर बेची गयी. भाजपा नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अभिजीत विश्वास उर्फ बॉबी ने डायमंड हार्बर के कालीतला आशुलिया थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया है।

नीट री-एग्जाम से पहले सरकार का बड़ा एक्शन!

पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम पर लगाई रोक..

नई दिल्ली/ एजेंसी

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के री-एग्जाम से पहले केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और अहम कदम उठाया है। परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराने के उद्देश्य से मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने स्पष्ट किया है कि यह सख्त फैसला फर्जी पेपर लीक की खबरों को रोकने के लिए लिया गया है। आगामी 21 जून को होने वाले नीट री-एग्जाम को देखते हुए यह फैसला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्व टेलीग्राम के माध्यम से छात्रों और उनके परिजनों को प्रश्नपत्र देने का झूठा लालच देकर ठग रहे थे। एनटीए के अनुसार यह रोक परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अफवाह को रोकने में पूरी तरह कारगर साबित होगी और छात्रों को राहत मिलेगी। इसके अलावा टेलीग्राम का खास मैसेज एडिट फीचर भी 30 जून तक के लिए पूरी तरह से बंद रखने का कड़ा आदेश दिया गया है। प्रशासन इस बार परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की कोई चूक या गलती बिल्कुल नहीं चाहता है। एनटीए के मुताबिक कई बड़े गिरोह टेलीग्राम चैनलों के जरिए परीक्षा के फर्जी पेपर बेचने का झूठा दावा कर रहे थे। Paper Leaked NEET, Re-NEET 2026 और Private Mafia जैसे कई चैनल बनाकर हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की भारी मांग की जा रही थी।

जेवर एयरपोर्ट पर इस ठाठ से पहुंचा पहला कमर्शियल विमान

लखनऊ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यात्री उड़ानों की शुरुआत हो गई है. इंडिगो की पहले दिन उद्घाटन के लिए तिहरा रूट तैयार किया है. पहली फ्लाइट लखनऊ से नोएडा पहुंची, जिसमें यूपी के 75 के करीब कारोबारी जेवर एयरपोर्ट पहुंचे. इसे वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया. वहीं शाम को नोएडा एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए उड़ान भरी जाएगी, जिसमें जेवर के 175 किसान लखनऊ जाएंगे. लखनऊ से नोएडा आने वाला विमान बेंगलुरू जाएगा. ऐसे में यह त्रिकोणीय रूट पूरा होगा. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के इतिहास में सबसे पहली लैंडिंग करने वाली उद्घाटन उड़ान लखनऊ से नोएडा पहुंची

दवाओं की बिक्री पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा अब कफ सिरप....

नई दिल्ली/ एजेंसी

देशभर में दवाओं की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब मेडिकल स्टोर से किसी भी प्रकार की सिरप, चाहे वह खांसी, सर्दी, बुखार या अन्य बीमारी से संबंधित हो, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीदी जा सकेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको लेकर एक नोटिफिक्केशन जारी किया है।9 जून को जारी इस नोटिफिक्केशन में सरकार ने बताया है कि खांसी की सिरप समेत सभी तरह की सिरप अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, दवा नियम 1945 में संशोधन करते हुए अनुसूची 'च' से 'सिरप' शब्द को हटा दिया गया है। पहले कुछ प्रकार की सिरप ऐसी श्रेणी में शामिल थीं जिन्हें बिना डॉक्टर की पर्ची के खरीदा जा सकता था। इन्हें ओवर-द-काउंटर दवाओं के रूप में बेचा जाता था। हालांकि, अब यह छूट समाप्त कर दी गई है। नए नियम के तहत मरीजों को किसी भी प्रकार की सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर द्वारा जारी वैध प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा। मेडिकल स्टोर संचालकों को भी बिना पर्ची के सिरप बेचने से बचने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि कई बार लोग खुद ही दवा लेकर इलाज शुरू कर देते हैं, जिससे गलत दवा सेवन, साइड इफेक्ट्स और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

यस बैंक घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई

ईडी का मुंबई और दिल्ली समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी की...

नई दिल्ली/ एजेंसी

यस बैंक से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी लोन ट्रांसफर मामले में प्रवर्तन निदेशालयने मुंबई, खंडाला और दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी की। जांच का केंद्र उन कथित सौदों पर है, जिनमें संकटग्रस्त संपत्तियों को कम कीमत पर हासिल करने, फर्जी दावों और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के जरिए फायदा पहुंचाने के आरोप हैं। ईडी के मुंबई जोनल ऑफिस-1 ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है। यह कार्रवाई मुंबई, खंडाला और दिल्ली में एक साथ की गई। जांच एजेंसी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाने की कोशिश की। मामला यस बैंक और कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के बीच कथित मिलीभगत से जुड़ा हुआ है। ईडी ने जिन संस्थाओं और लोगों के परिसरों पर छापेमारी की, उनमें सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और इनके प्रमोटर, निदेशक तथा कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा यस बैंक के एक पूर्व कर्मचारी को भी जांच के दायरे में लिया गया है। एजेंसी को संदेह है कि इन संस्थाओं और व्यक्तियों की भूमिका संदिग्ध वित्तीय लेनदेन में रही हो सकती है। जांच का मुख्य आधार यस बैंक के एक बड़े लोन खाते से जुड़ा है। ईडी के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान मेसर्स मैकस्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लोन और इसी तरह के अन्य कर्ज खातों के असाइनमेंट में कथित अनियमितताएं हुई थीं। आरोप है कि इन

लोन खातों को ऐसे तरीके से ट्रांसफर किया गया, जिससे कुछ पक्षों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके। अब एजेंसी इस पूरे वित्तीय ढांचे की गहराई से जांच कर रही है। ईडी को शक है कि कुछ एआरसी और यस बैंक के बीच कथित मिलीभगत के तहत सर्कुलर ट्रांजैक्शन किए गए। इन लेनदेन के जरिए संकटग्रस्त परिसंपत्तियों पर धोखाधड़ी से नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की गई। जांच एजेंसी यह भी देख रही है कि कहीं नीलामी के दौरान संपत्तियों का मूल्य जानबूझकर कम तो नहीं आंका गया था। इसके साथ ही फर्जी या बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए दावों की भी जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच एनसीएलटी की कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस से जुड़े पहलुओं तक पहुंच गई है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं लेनदारों के वोटिंग अधिकारों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता प्रभावित तो नहीं की गई। तलाशी अभियान का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े ठोस सबूत जुटाना है। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

भारतमाला परियोजना में नया विवाद : सिवनीकला गांव में फर्जी नामांतरण कर करोड़ों के मुआवजा घोटाले का आरोप

रायपुर। भारतमाला परियोजना में कथित अनियमितताओं का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब धमतरी जिले के सिवनीकला गांव में भी जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत एसीबी/ईओडब्ल्यू से की है। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण बयान दर्ज कराने एसीबी/ईओडब्ल्यू कार्यालय पहुंचे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि भारतमाला परियोजना के तहत अधिग्रहित जमीनों में फर्जी नामांतरण और अवैध बंटवारा कर करोड़ों रुपये का मुआवजा हासिल किया गया है। शिकायत में दावा किया गया है कि गांव के 17 से 18 खसरों को करीब 90 टुकड़ों में विभाजित कर फर्जी तरीके से रिकॉर्ड तैयार किए गए।

जलभराव और आवागमन की समस्या होगी दूर, पटरीपार के चार वार्डों में शुरू होंगे निर्माण कार्य, विकास की रफ्तार तेज, नाली एवं पुलिया निर्माण कार्यों का शुभारंभ

75 लाख रुपये से अधिक के नाली एवं पुलिया निर्माण कार्यों का भूमिपूजन, जल्द शुरू होंगे निर्माण कार्य

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा शहर के पटरीपार क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और नागरिकों की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। महापौर अलका बाघमार ने लोककर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वार्ड क्रमांक 14, 15, 16 एवं 44 में 75 लाख रुपये से अधिक की लागत से होने वाले नाली एवं पुलिया निर्माण कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया। भूमिपूजन कायक्रम के दौरान क्षेत्रीय नागरिकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। लंबे समय से जल निकासी और आवागमन की समस्याओं से जूझ रहे लोगों ने विकास कार्यों की स्वीकृति एवं भूमिपूजन पर महापौर एवं निगम प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

चार वार्डों में होंगे विकास कार्य, जल निकासी समस्या से मिलेगी राहत-भूमिपूजन अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 गुरु घासीदास वार्ड में हिरामन साहू के घर से रानू के घर तक तथा पवन के घर से परऊ यादव के घर के पास तक लगभग 19 लाख रुपये की लागत से नाली निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 14 सिकोला भाठा की विभिन्न गलियों में 18 लाख रुपये की लागत से नाली निर्माण कार्य होगा। वार्ड क्रमांक 15 सिकोला बस्ती में मानिकपुरी के घर तक तथा निर्मला के घर से प्रकाश के घर तक नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य लगभग 18 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा। वहीं वार्ड क्रमांक 16 सिकोला बस्ती कर्मचारी नगर में साहू भवन से मुख्य नाला तक 20 लाख रुपये की लागत से नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य संपादित किया जाएगा। इन सभी कार्यों के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में जलभराव की समस्या दूर होगी, बारिश के दौरान जल निकासी बेहतर होगी तथा नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।विकास कार्यों से बदलेगी पटरीपार क्षेत्र की तस्वीर : महापौर अलका बाघमार-इस अवसर पर महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर के सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सड़क, नाली और पुलिया निर्माण के कार्य लगातार स्वीकृत किए जा रहे हैं। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि बरसात के मौसम में जलभराव और आवागमन की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से इन कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी तथा पटरीपार क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का स्तर और बेहतर होगा। भूमिपूजन कार्यक्रम में पार्षद ललिता ठाकुर, युवराज कुंजाम, खिलावन मटियारा, रंजीता पाटिल, सावित्री दमाहे, भाजपा जिला प्रवक्ता अरुण सिंह, मंडल अध्यक्ष मनमोहन सिंह, सहायक अभियंता संजय ठाकुर,उप अभियंता सिद्धार्थ साहू सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने विकास कार्यों के लिए नगर निगम एवं महापौर का आभार व्यक्त करते हुए निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने की अपेक्षा जताई।

शहर के प्रत्येक वार्ड में विकास की रफ्तार तेज-नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा वर्तमान में विभिन्न वार्डों में सड़क, नाली, पुलिया, पेयजल एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य लगातार स्वीकृत और प्रारंभ किए जा रहे हैं। निगम का लक्ष्य शहर के प्रत्येक वार्ड में नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाकर समग्र विकास को गति देना है, ताकि आमजन को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

वार्ड 30 और 31 में विकास को मिली रफ्तार, 82 लाख से अधिक के निर्माण कार्य होंगे शुरू

महापौर एवं सभापति कराया 82 लाख के कार्यों का शुभारंभ

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा शहर के बाजार क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं नागरिकों की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 82 लाख रुपये से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। महापौर अलका बाघमार ने वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद एवं सभापति श्याम शर्मा, लोककर्म विभाग प्रभारी देव नारायण चंद्राकर, सांस्कृतिक विभाग प्रभारी एवं वार्ड क्रमांक 31 की पार्षद हर्षिका संभव जैन सहित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों की उपस्थिति में आरसीसी सड़क, नाली एवं पुलिया निर्माण कार्यों का विधिवत शुभारंभ किया। भूमिपूजन के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 30 में तेजपाल के निवास से डिसेंट सैलून तक 25 लाख रुपये की लागत से नाली निर्माण तथा तमेरपारा के विभिन्न स्थानों पर 17 लाख रुपये की लागत से नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य किए जाएंगे। वहीं वार्ड क्रमांक 31 में सिंडिकेट बैंक से स्वाध्याय भवन एवं सिद्धार्थ नगर बस्ती तक 12 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण, आपापूरा से आबकारी कार्यालय, रजा खोखर कार्यालय, गवलीपारा होते हुए वर्धमान स्थापक भवन तक 15 लाख रुपये की लागत से आरसीसी सड़क निर्माण तथा हनुमान नाला से गुप्ता कॉम्प्लेक्स तक 13 लाख रुपये की लागत से नाली निर्माण कार्य कराया जाएगा। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि निगम का लक्ष्य प्रत्येक वार्ड में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर नागरिकों को बेहतर आवागमन एवं जल निकासी व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय नागरिकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। लंबे समय से जल निकासी एवं आवागमन की समस्याओं से जूझ रहे लोगों ने विकास कार्यों की स्वीकृति और शुभारंभ पर महापौर के प्रति आभार व्यक्त किया।इस अवसर पर एमआईसी सदस्य शेखर चंद्राकर, नीलेश अग्रवाल, संभव जैन, रजा खोखर सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

महापौर निधि के कार्यों की हुई समीक्षा, अधिकारियों से मांगी प्रगति रिपोर्ट, फील्ड में रहकर कार्यों की निगरानी करें अधिकारी, निर्माण सामग्री की जांच के दिए निर्देश

विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयसीमा से कोई समझौता नहीं : महापौर अलका बाघमार

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग की महापौर अलका बाघमार की अध्यक्षता में महापौर कक्ष में शहर में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम क्षेत्र में चल रहे एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत व महापौर निधि के किए जा रहे कार्यों, सड़क डामरीकरण, सीमेंट कांक्रीट सड़कों, नाली-पुलिया निर्माण, स्ट्रीट लाइट, पेवर ब्लॉक, पेयजल व्यवस्था एवं शहर के सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। महापौर अलका बाघमार ने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की तथा कार्यों को निर्धारित समयसीमा एवं मानक गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने महापौर निधि से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से जानकारी ली कि एक वर्ष में प्राप्त 1 करोड़ 12 लाख रुपये की राशि से कितने कार्य पूर्ण हुए हैं तथा कितने कार्य प्रगतिरत अथवा शेष हैं। उन्होंने पुराने कार्यों के साथ-साथ नवीन स्वीकृत कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए तथा ठेकेदारों को निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं फील्ड में उपस्थित रहकर निर्माण कार्यों की सतत निगरानी करें ताकि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिल सकें। भूमिपूजन के उपरांत संबंधित स्थल पर शिलापट्ट स्थापित करने तथा कार्य की प्रगति का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड संधारित कर जानकारी साझा करने के भी निर्देश दिए गए। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि शहर के विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी अधिकारी एवं निर्माण एजेंसियां समन्वय के साथ कार्य करें। लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर ने कहा कि नगर निगम द्वारा संचालित विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

जनहित के सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कर नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में निगम के संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक के दौरान लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर,शेखर चन्द्राकर, ज्ञानेश्वर ताम्रकर,कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा, मोहम्मद सलीम सिद्दीकी, सहायक अभियंता संजय ठाकुर, सहायक अभियंता हरिशंकर साहू, पंकज साहू, विनोद मांझी,अपर्णा मिश्रा सहित अधिकारी/ कर्मचारी मौजूद रहे।

उधारी रकम वसूलने घर घुसकर मारपीट

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर जिले में गुण्डा तत्वों एवं असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने उधारी रकम की जबरन वसूली के लिए घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने वाले गुण्डा बदमाश कपिल सोलंकी एवं उसके दो साथियों मनीष परियानी और गिरीश माखीजा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। मामले में आशीर्वाद पूरम कॉलोनी रायगढ़ निवासी कमलेश सिंह उम्र 52 वर्ष द्वारा 13 जून को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह कोयला ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करता है। प्रार्थी ने बताया कि कुडेकेला निवासी ललेश अग्रवाल का लगभग 07 लाख रुपये भुगतान आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पिछले करीब तीन वर्षों से नहीं कर पाया है। प्रार्थी के अनुसार, 11 जून की दोपहर गुण्डा बदमाश कपिल सोलंकी अपने हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर अपने साथी मनीष परियानी एवं गिरीश माखीजा के साथ उसके घर में जबरन घुस आया। आरोपियों ने पीड़ित को धमकाते हुए कहा कि तू हम लोगों को नहीं जानता है, तेरा मर्डर करवा देंगे।ष् इसके बाद ललेश अग्रवाल का पैसा वापस करने की बात कहते हुए पीड़ित से 10 लाख रुपये की मांग की गई तथा हाथ-मुक्के और डंडे से उसकी मारपीट की गई। पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। गुण्डा बदमाश कपिल सोलंकी की गतिविधियों की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के संज्ञान में आने पर उन्होंने कोतवाली पुलिस को तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। कोतवाली पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी गई। ईवाई के दौरान मुख्य आरोपी कपिल सोलंकी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई।

विचाराधीन बंदी की अस्पताल में मौत मामले ने पकड़ा तूल, परिजनों ने निष्पक्ष जांच की उठाई मांग, हिरासत में पुलिस व जेल में मारपीट का किया दावा

रायगढ़। जिला जेल रायगढ़ में न्यायिक हिरासत के दौरान एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजनों ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधायक, कलेक्टर, एसपी और कोतरारोड़ थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार पुलिसकर्मियों और जेल अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज करने तथा परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की है। रायगढ़ जिला मुख्यालय रविवार की सुबह गांव के ग्रामीण भारी संख्या में पहुंचे यहां उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि ग्राम नावापारा निवासी 30 वर्षीय संजय बघेल को 10 जून को कोतरारोड़ पुलिस द्वारा एक शराब संबंधी मामले में गिरफ्तार किया गया था। परिजनों का आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिसकर्मियों ने संजय बघेल के साथ मारपीट की और मामले को रफा-दफा करने के लिए कथित रूप से दो लाख रुपये की मांग की गई। आरोप है कि बाद में सौदेबाजी के तहत 40 हजार रुपये लेने के बावजूद उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया। परिवार का दावा है कि संजय बघेल पूरी तरह स्वस्थ था और उसे किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं थी। वह अपने माता-पिता, पत्नी और दो नाबालिग बेटियों का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जेल और पुलिस प्रशासन की हिरासत में उसके साथ गंभीर मारपीट की गई, जिसके कारण उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और मुंह से खून निकल रहा था। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि संजय की मौत की सूचना परिजनों को समय पर नहीं दी गई। परिवार का आरोप है कि मौत के बाद पहले उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया और बाद में सूचना दी गई, जिससे पूरे मामले पर संदेह और गहरा गया है। परिजनों का कहना है कि जब उन्हें शव दिखाया गया तब शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान दिखाई दिए, जिनके फोटो और वीडियो उनके पास मौजूद हैं। मृतक के परिवार ने मांग की है कि पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज की जांच, न्यायिक एवं स्वतंत्र एजेंसी से जांच तथा दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।

फर्जी दस्तावेजों से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के खेल की जांच तेज, ट्रेवल्स एजेंसी में पुलिस-आरटीओ की संयुक्त दबिश करीब 180 दस्तावेजों की हो रही तस्दीक

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम विदित हो कि बीते 17 अप्रैल को नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा की अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम में छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पुलिस, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर समय-समय पर संयुक्त जांच एवं कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

उक्त निर्देशों के पालन में संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ नवसीखिया चालक हेवी वाहन चलाने के लिए जारी लाइसेंसों का उपयोग कर भारी वाहनों का संचालन कर रहे हैं तथा 11 जून को पुलिस को लिखित आवेदन इस आशय का प्राप्त हुआ है कि स्थानीय स्तर पर संचालित बाबा ट्रेवल्स नामक संस्थाएजेंसी द्वारा कथित रूप से ओडिशा एवं अन्य राज्यों के निवासियों के लिए फर्जी एवं भ्रामक दस्तावेज तैयार कर उन्हें रायगढ़, छत्तीसगढ़ का निवासी दर्शाते हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का कार्य किया जा रहा है। प्राप्त शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर सत्यापन के लिए नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा एवं यातायात उप पुलिस अधीक्षक उत्तम प्रताप सिंह के नेतृत्व में आरटीओ एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बाबा ट्रेवल्स में दबिश दी गई। जांच के दौरान प्राप्त दस्तावेजों में कई आवेदकों के पते समान पाए गए। प्रारंभिक जांच मंस यह तथ्य सामने आ रहे हैं कि बाहरी राज्यों के आवेदकों के लिए स्थानीय स्तर पर किरायानामा एवं शपथ-पत्र तैयार कर उन्हें रायगढ़ का निवासी दर्शाते हुए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कराया गया। जांच के दौरान यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया के तहत निर्धारित परीक्षण में वास्तविक आवेदक के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को शामिल कर परीक्षण दिलाए जाने के बाद लाइसेंस जारी कराए गए हो सकते हैं। इस संबंध में जांच टीम द्वारा लगभग 180 लाइसेंसधारियों के दस्तावेजों की विस्तृत जांच एवं सत्यापन किया जा रहा है।

अवैध बोर खनन करते हुए सुमित्रा बोरवेल की मशीन जब्त

रायगढ़। भीषण गर्मी और लगातार गिरते भू-जल स्तर के बीच प्रशासन ने अवैध बोर खनन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। घरघोड़ा तहसील के ग्राम रायकेरा में अवैध रूप से बोर खनन की सूचना पर तहसीलदार मनोज कुमार गुप्ता ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी की और सुमित्रा बोरवेल के वाहन को जब्त कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। जिले में जल संकट को देखते हुए नए बोरवेल खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद कुछ लोग नियमों को दरकिनार कर भू-जल दोहन में लगे हुए हैं। ग्राम रायकेरा में भी प्रतिबंध के बावजूद बोर खनन किए जाने की सूचना मिलने पर प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। वर्तमान में क्षेत्र भीषण गर्मी की चपेट में है और भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे समय में जल संरक्षण को लेकर प्रशासन पूरी तरह गंभीर है।

प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि प्रतिबंध अवधि में किसी भी प्रकार का नया बोरवेल नहीं खोदा जाएगा। इसके बावजूद सुमित्रा बोरवेल द्वारा किए जा रहे अवैध खनन प्रयास पर कार्रवाई कर प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है कि नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए अवैध खनन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने की मांग की है। तहसीलदार की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में भू-जल संरक्षण को लेकर प्रशासन की गंभीरता साफ नजर आई है।

अग्रसेन चौक से हटाए गए यातायात बाधित ठेले-खोमचे, निगम की सख्त कार्रवाई

अतिक्रमणकारियों को चेतावनी : दोबारा सड़क घेरने पर होगी सामान जब्ती व जुर्माना

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र अंतर्गत शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर अग्रसेन चौक एवं उसके आसपास सड़क एवं आवागमन क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे ठेले-खोमचों को हटाने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई अतिक्रमण अधिकारी परमेश्वर के नेतृत्व में निगम अमले एवं पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न हुई। अभियान के दौरान सड़क किनारे एवं चौक क्षेत्र में यातायात बाधित कर रहे सभी ठेले-खोमचों को हटवाया गया, जिससे आवागमन सुचारू हो सके तथा नागरिकों को जाम एवं असुविधा से राहत मिल सके। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण अधिकारी परमेश्वर ने संबंधित ठेला संचालकों एवं व्यापारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़क, चौक एवं आवागमन क्षेत्र में दोबारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था बाधित न करें। यदि भविष्य में पुनः अतिक्रमण करते पाए गए तो निगम द्वारा सामान जब्त करने के साथ-साथ नियमानुसार जुर्माना एवं कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना तथा नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध कराना है। निगम प्रशासन द्वारा प्रमुख चौक-चौराहों, बाजार क्षेत्रों एवं व्यस्त मार्गों पर नियमित निगरानी रखी जा रही है। शहर में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थलों एवं सड़क मार्गों पर अतिक्रमण न करें तथा शहर को व्यवस्थित, स्वच्छ और यातायात बाधा मुक्त बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।

संक्षिप्त समाचार

राम मंदिर से पूजन सामग्री ले गईं दो महिलाएं, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

रायपुर। दल्लीराजहरा के राम मंदिर में हुई चोरी की घटना ने श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया है। जहां भक्त पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं, वहीं अज्ञात दो महिलाओं ने मंदिर की पूजन सामग्री और बर्तनों पर हाथ साफ कर दिया। राहत की बात यह रही कि उनकी पूरी करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुबह मंदिर के पुजारी ने पूजा के दौरान कुछ सामग्री और बर्तनों को गायब पाया। जांच करने पर चोरी की आशंका हुई, जिसके बाद तत्काल दल्लीराजहरा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज में दो महिलाएं मंदिर परिसर में संदिग्ध गतिविधियां करती दिखाई दे रही हैं। फुटेज के अनुसार दोनों महिलाएं पहले परिसर का जायजा लेती हैं, फिर धीरे-धीरे पूजन सामग्री और बर्तनों को समेटकर वहां से निकल जाती हैं। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। आसपास के क्षेत्रों और बाजारों में भी महिलाओं के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। प्रारंभिक जांच में पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और कुछ बर्तनों के चोरी होने की पुष्टि हुई है, जबकि चोरी गए सामान का पूरा विवरण तैयार किया जा रहा है।

तलवार लेकर आतंक फैलाने वाला युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे

रायपुर। डूमर तालाब क्षेत्र में हाथ में तलवार लहराकर राहगीरों के बीच दहशत फैलाने वाले युवक का आतंक आखिरकार पुलिस ने खत्म कर दिया। आमानाका थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर-दबोचा और उसके कब्जे से अवैध धारदार तलवार बरामद की। जानकारी के अनुसार 13 जून 2026 की शाम पुलिस की नियमित पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली कि एक युवक खुलेआम लोहे की तलवार लेकर लोगों को डरा-धमका रहा है। उसकी हरकतों से आसपास के लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गवाहों की मौजूदगी में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक धारदार लोहे की तलवार बरामद हुई, जिसे वह सार्वजनिक स्थान पर लहरा रहा था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी की हरकतें न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती थीं, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रही थीं। इसी आधार पर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई।

एम्बुलेंस पर चालक पर हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। धमतरी जिले में मानवता की सेवा में लगी एम्बुलेंस पर हमला करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों ने एम्बुलेंस चालक से मारपीट की और वाहन में तोड़फोड़ कर लाखों रुपये की क्षति पहुंचाई थी। घटना 8 जून की रात की बताई जा रही है, जब उमरदा गौठान के पास एक सड़क हादसा हुआ था। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिलने पर वंदे मातरम परिवार समिति की एम्बुलेंस मौके पर राहत कार्य के लिए पहुंची थी। एम्बुलेंस चालक राधेश्याम निर्मलकर भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे थे।

हितग्राहियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का मिला लाभ

मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 14 वें चरण का शुभारंभ

■ वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने बीजापुर जिले को 18 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात

रायपुर/ संवाददाता

वन एवं जलवायु परिवर्तन, सहकारिता, परिवहन एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने जिले को 18 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 14वें चरण का शुभारंभ करते हुए 16 करोड़ 58 लाख रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन तथा 2 करोड़ 9 लाख रुपये के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री एवं प्रमाण-पत्र भी वितरित किए गए। वन मंत्री श्री कश्यप ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं अधोसंरचना विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें मिरतुर और बेदरे में ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण, उसूर में वरिष्ठ कृषि अधिकारी भवन, आवापल्ली एवं कुटरू में शासकीय महाविद्यालय भवन, भैरमगढ़ महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्ष निर्माण तथा दुगईगुड़ा से चिंताकोंटा तक सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं से शिक्षा, कृषि सेवाओं और आवागमन सुविधाओं को मजबूती मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति प्राप्त होगी। लोकार्पित कार्यों में जिला अस्पताल परिसर में रैन बसेरा, दाल-भात केंद्र, अत्याधुनिक अटल आरोग्य लैब, कार्यालय सह गोदाम भवन,

विद्यालय भवन, पंचायत भवन, पुलिया निर्माण तथा शैक्षणिक संस्थानों में तार फेंसिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। अटल आरोग्य लैब में अब 134 प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। कार्यक्रम के दौरान मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 14वें चरण का शुभारंभ किया गया। अभियान के माध्यम से जिले में मलेरिया नियंत्रण, समय पर जांच और उपचार के लिए विशेष गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जिससे लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। स्वामित्व योजना के अंतर्गत वनाधिकार पट्टों का वितरण किया गया। वहीं निक्षय योजना के तहत पोषण आहार फूड बॉक्स, पुनर्वासित परिवारों को आयुष्मान कार्ड, गर्भवती महिलाओं को जच्चा-बच्चा कार्ड तथा दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राइसाइकिल प्रदान की गई। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि बीजापुर में अब विकास की नई धारा बह रही है। पहले जिन क्षेत्रों तक पहुंचना कठिन था, वहां आज सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनकल्याण और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, महतारी वंदन योजना तथा तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाएं लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं से समाज के सभी वर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बीजापुर आने वाले वर्षों में विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इस अवसर पर बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जानकी कोरसा, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती गीता सोम पुजारी, कलेक्टर श्री विश्वदीप, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव, डीएफओ डॉ. सागर यादव, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता चौबे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

अमृत मिशन से सुदृढ़ हो रही पेयजल व्यवस्था.....

रायपुर। संवाददाता

नगर पालिक निगम राजनांदगांव द्वारा राजनांदगांव शहर में पेयजल व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यवस्थित बनाने के लिए अमृत मिशन अंतर्गत पाइपलाइन विस्तार, ओवरहेड टंकी निर्माण तथा अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से बड़ी संख्या में नागरिकों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध हुई है तथा शेष क्षेत्रों में भी व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य जारी है। शहर के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी का दबाव कम होने के कारण कहीं-कहीं जलापूर्ति अपेक्षाकृत कम हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न वार्डों में पाइपलाइन विस्तार का कार्य प्रगतिरत है। साथ ही पेयजल प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार नियमित रूप से टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं सार्वजनिक आयोजनों के दौरान भी मांग के अनुरूप जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा कॉलोनियों के संपवेल में भी टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। शहर के निरंतर विस्तार तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई पानी टंकियों के निर्माण एवं अतिरिक्त पाइपलाइन विस्तार कार्यों को शासन से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से शहर की पेयजल व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

स्कूलों में आरएसएस का एजेंडा नहीं थोपा जाना चाहिए-कांग्रेस

रायपुर। संवाददाता

स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों में बच्चों के लिए तीन विभिन्न प्रकार के मंत्र का गान अनिवार्य किया जाना बेहद ही आपत्तिजनक है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राज्यगीत तक का गायन तो उचित है लेकिन दीप मंत्र, सरस्वती मंत्र, भोजन के समय भोजन मंत्र इन सब की अनिवार्यता क्यों की गयी है? सरकार स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिर बनाने पर तुली है। आरएसएस के एजेंडे को सरकारी स्कूलों में थोपा जाना गलत है। सरकारी स्कूलों में देश के हर धर्म, हर जाति और हर साम्प्रदायिक के लोग पढ़ने आते है, हर वर्ग के पढ़ाई करते है। इस निर्णय से कुछ लोगों की आपत्ति होगी, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होगी। हिन्दुस्तान सर्वधर्म समभाव वाला देश है। संवैधानिक रूप से भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। स्कूलों में धर्म विशेष के आधार पर शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आजादी के बाद से हमारी शिक्षा प्रणाली में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार के साथ शिक्षा दी जाती रही है। सामाजिक अध्ययन, संस्कृत एवं मातृभाषा जैसे विषयों में विद्यार्थी सभी सामाजिक एवं धार्मिक परंपराओं का अध्ययन करते रहे है। किसी धर्म के साथ भेदभाव का अध्ययन नहीं कराया गया। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश में अलग-अलग धर्मावलंबी अपनी धार्मिकता के आधार शैक्षणिक संस्थान चलाते है, लेकिन सरकारी स्कूलों में मंत्राचार को अनिवार्य करने से दूसरे धर्म के लोगों को ठेस पहुंचेगी। ऐसे में मुस्लिम धर्म के लोग कुरान की आयात तथा सिख धर्म के लोग गुरुवाणी तथा ईसाई धर्म के लोग बाइबल के अंशों को भी वाचन करने की मांग करेंगे। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार शिक्षा को शिक्षा ही रहने दे उसे धार्मिक सांचे में ढालने का प्रयास मत करे।

जल जीवन मिशन सुकली बना हर घर जल का आदर्श ग्राम

■ सरपंच और ग्रामीणों की सहभागिता से हर घर तक पहुंचा स्वच्छ पेयजल

रायपुर/ संवाददाता

शासन द्वारा महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन घर-घर नल कनेक्शन पहुंचाकर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। योजना के तहत लोरमी विकासखण्ड के ग्राम सुकली में सामुदायिक सहभागिता, पारदर्शी नेतृत्व और ग्रामीणों की जिम्मेदारी ने जल प्रबंधन की एक प्रेरणादायक मिसाल स्थापित की है। ग्राम सुकली में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। ग्राम की सरपंच एवं ग्राम जल स्वच्छता समिति की अध्यक्ष श्रीमती गीता बाई के नेतृत्व में गांव को हर घर जल ग्राम के रूप में विकसित किया गया है। आज गांव के सभी परिवार नियमित रूप से नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल प्राप्त कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्राम सुकली में न केवल हर घर तक जल पहुंचा है, बल्कि सामुदायिक स्वामित्व और आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल भी कायम की है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका सतत एवं आत्मनिर्भर संचालन है। श्रीमती गीता बाई ने ग्रामीणों के सहयोग से गांव में जल कर व्यवस्था लागू करने की पहल की। इस पहल को ग्रामवासियों का भरपूर समर्थन मिला और सभी परिवार समय पर जल कर का भुगतान करने लगे। जल कर से प्राप्त राशि का उपयोग पाइपलाइन मरम्मत, मोटर-पंप के रखरखाव तथा पंप ऑपरेटर के मानदेय के भुगतान में किया जा रहा है। इस व्यवस्था के कारण योजना के संचालन के लिए बाहरी संसाधनों पर निर्भरता कम हुई है और जलापूर्ति व्यवस्था निरंतर एवं सुचारु रूप से संचालित हो रही है। ग्रामीणों में जल संरक्षण एवं संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हुई है। श्रीमती गीता बाई का कहना है कि विकास तभी स्थायी बनता है जब समुदाय स्वयं उसकी जिम्मेदारी उठाए। उनके नेतृत्व, पारदर्शी कार्यप्रणाली और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी ने सुकली को जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित किया है।

नदियों के पुनरूद्धार एवं पुनर्जीवित करने संबंधी राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित राज्य की प्रमुख नदियों के पुनरूद्धार एवं पुनर्जीवित करने गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में प्रवाहित हो रही नदियों के पुर्नजीवन हेतु किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। नदियों का संरक्षण से जन स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में बैठक में जिलों के कलेक्टरों से नदियों के कैचमेंट एरिया में बनायी गई विविध जल संरक्षण एवं संचयन की कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा है कि हाईकोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार नदियों के पुनर्जीवित एवं पुनरूद्धार के कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों से नदियों के कैचमेंट एरिया में ऐसे जनउपयोगी कार्यों को लिया जाए जो भविष्य में नदियों के आस-पास रहने वाले लोगों की जरूरतों के अनुरूप हो। मुख्य सचिव ने नदियों के कैचमेंट एरिया में किए जाने वाले कार्यों से स्थानीय सरपंचों एवं जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से जोड़ने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा है कि जिले से उद्गम होने वाली नदियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी रखी जाए। जिससे नदियों के बारे में छात्रों को जानकारी मिले। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्कूलों के छात्र-छात्राओं का भ्रमण नदियों के उद्गम स्थल पर कराया जाए और नदियों की जानकारी के संबंध में छात्रों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। कलेक्टर ने नदियों के उद्गम स्थलों पर मेला उत्सव जैसे आयोजनों को करने के लिए भी कहा। बैठक में कलेक्टर रायगढ़, कोरबा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, सरगुजा, कोरिया, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, गरियाबंद और धमतरी के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिले में स्थित नदियों की वास्तविक स्थिति और संचालित कार्ययोजनाओं एवं परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

बीएसयूपी कॉलोनी में पुलिस का बड़ा सर्च अभियान.....

रायपुर। राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने बीएसयूपी कॉलोनी में व्यापक आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 100 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने 300 से अधिक मकानों की सघन जांच कर संदिग्ध व्यक्तियों, किरायेदारों और निगरानी बदमाशों का सत्यापन किया। पुलिस उपायुक्त (वेस्ट जोन) संदीप पटेल के निर्देश पर थाना सरस्वती नगर, आमानाका और न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित बीएसयूपी कॉलोनी में यह विशेष अभियान संचालित किया गया। अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (वेस्ट जोन), सहायक पुलिस आयुक्तों और संबंधित थाना प्रभारियों ने किया। सुबह 8 बजे शुरू हुए अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने कॉलोनी के विभिन्न ब्लॉकों, मकानों और सार्वजनिक स्थलों की गहन जांच की। क्षेत्र में निवासरत गुण्डा-बदमाशों, निगरानी बदमाशों, आदतन अपराधियों तथा अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की पड़ताल की गई। साथ ही बाहर से आकर किराये या अस्थायी रूप से रह रहे लोगों के पहचान दस्तावेजों का भी सत्यापन किया गया। पुलिस ने घर-घर पहुंचकर निवासियों से आवश्यक जानकारी एकत्र की और सुरक्षा संबंधी सुझाव दिए। अभियान के दौरान किरायेदारों, बाहरी व्यक्तियों और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी गई। पुलिस अधिकारियों ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी।

सड़कों-पुलों के निर्माण में देरी पर बिफरे डिप्टी सीएम

मंत्री ने दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त, आठ को नोटिस जारी

रायपुर। संवाददाता

उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव द्वारा सड़कों व पुलों के निर्माण की धीमी गति पर गहरी नाराजगी जाहिर करने और ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश के बाद विभाग ने दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त कर दिए हैं। लोक निर्माण विभाग ने कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। वहीं पूर्व में दो ठेकेदारों को जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब का परीक्षण कर ठेकेदार के विरूद्ध कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मंगाया गया है। लोक निर्माण विभाग ने 10 जून को भी राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर केशलूर-जगदलपुर मार्ग में किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलवे लाइन के ऊपर केशलूर के पास बन रहे फ्लेरलेन रेलवे ओवरब्रिज में काम की प्रगति मंजूर किए गए निर्माण कार्यक्रम से काफी पीछे होने और तय किए गए माइलस्टोन्स के अनुरूप नहीं होने पर ठेकेदार मेसर्स अशोक कुमार मित्तल को नोटिस जारी कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पिछले सप्ताह चार दिनों के बस्तर प्रवास के दौरान अपने चारों विभागों के कार्यों का निरीक्षण कर गहन समीक्षा की थी। उन्होंने निरीक्षण और बैठकों के दौरान सड़कों व पुलों के निर्माण की धीमी प्रगति पर अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर गहरी नाराजगी जताई थी। काम में लापरवाही, देरी और अनुबंध के अनुसार अपेक्षित तेजी नहीं लाने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने चार पुलों के निर्माण की धीमी प्रगति पर ठेकेदार मेसर्स गुप्ता कन्सट्रक्शन कंपनी का पंजीयन दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है। कंपनी द्वारा भवरडींग नदी पर अदनार-तोतर मार्ग, कोंडागांव के घोटिया-मुंडा-चांदाबेड़ा मार्ग और बड़े राजपुर विकासखंड के पलना-मरीगांव-कुंडई मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। कंपनी कबीरधाम जिले के बांटीपथरा से कुई (दमगढ़) मार्ग में हॉफ नदी पर भी उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कर रही है। चारों कार्यस्थलों पर कंपनी का काम अपेक्षित गति से काफी पीछे है। विभाग ने कांकेर के आमाबेड़ा-सेमर गांव सड़क पर नेरूल नदी तथा बोड़ागांव-खासगांव-तरादुल मार्ग में डुमरीकेल नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच

मार्ग के कार्य में लेटलतीफी पर ठेकेदार निर्भय राम साहू का पंजीयन आगामी दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है। विभाग द्वारा प्रगति की लगातार समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने के लिए बार-बार निर्देशित और नोटिस जारी करने के बावजूद इन दोनों ठेकेदारों के काम की गति असंतोषजनक है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने नारायणपुर-सोनपुर-मरोदा मार्ग के चौड़ीकरण व सुधार कार्य की धीमी गति पर ठेकेदार पंकज हालदार को पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस के उत्तर का परीक्षण कर कार्रवाई के लिए बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मंगाया है। प्रमुख अभियंता ने सुकमा में पैकपारा-धनीकोड़ता मार्ग तथा केरलापाल-पटेलपारा-सिरसट्टी सड़क के कार्य में भी अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर ठेकेदार आशीष भदौरिया को पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब का परीक्षण कर कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मंगाया है। विभाग ने कांकेर-अमोड़ा-नरहरपुर मार्ग के ठेकेदार मेसर्स बीएमएस प्रोजेक्ट, कोंडागांव में हडेली-कुदूर मार्ग के ठेकेदार मेसर्स सुराना एंड कंपनी और जगदलपुर-चित्रकोट मार्ग के ठेकेदार मेसर्स एसके अरोरा को कार्यों में धीमी प्रगति के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कार्यस्थलों पर काम की प्रगति मंजूर किए गए निर्माण कार्यक्रम से काफी पीछे होने और तय किए गए माइलस्टोन्स (महत्वपूर्ण पड़ावों) के अनुरूप नहीं होने पर सुकमा के चिंतलनार-मरियागुड़म सड़क के ठेकेदार के. मोहन रेड्डी, ट्रांससॉफ्ट इन्फ्रा और मेसर्स राघव कन्सट्रक्शन, कोंटा-गोलापल्ली मार्ग के ठेकेदार मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स राघव कन्सट्रक्शन तथा भेन्जी-चिंतागुफा सड़क का निर्माण कर रहे ठेकेदार के. मोहन रेड्डी एवं गोविन्द सिंह देशमुख को लोक निर्माण विभाग के सुकमा संभाग के कार्यपालन अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने कहा है कि सड़कों व पुलों के निर्माण में गुणवत्ता और समय-सीमा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी प्रकार की लेट-लतीफी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्यों के पूरे नहीं होने से लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है।

संपादकीय

लोकतंत्र एक मजबूत विपक्ष के मुखर स्वर से ही जीवित रहता है

माना जा रहा था कि कुछ दलों की नाराजगी का असर बैठक पर पड़ सकता है, लेकिन इसमें शामिल होने वाले दलों के बीच कई मुद्दों पर साझा अभियान चलाने पर सहमति बनी। इसमें कोई दोराय नहीं कि विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' के सामने फिलहाल बहुस्तरीय चुनौतियां खड़ी हैं और संगठित होकर इनका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मगर पिछले कुछ समय से 'इंडिया' के कुछ घटकों ने गठबंधन के दायित्वों से जुड़े जैसे सवाल उठाए हैं, उन पर विचार करके आगे की दिशा तय करने की चुनौती शायद सबके लिए अहम है।गौरतलब है कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों और उसके बाद नीट-यूजी 2026 के प्रश्नपत्र लीक होने सहित कई व्यापक महत्त्व के मुद्दों पर जनता के भीतर असंतोष के स्वर तीखे होने के बीच सोमवार को 'इंडिया' गठबंधन की बैठक हुई। माना जा रहा था कि कुछ दलों की नाराजगी का असर बैठक पर पड़ सकता है, लेकिन इसमें शामिल होने वाले दलों के बीच कई मुद्दों पर साझा अभियान चलाने पर सहमति बनी।मुख्य रूप से एसआइआर और चुनावों में वोटों की गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखने के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सभी दल सहमत थे। नाजुक आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई और समाज के कमजोर तबकों के मुद्दों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की गई।हालांकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस ने जिस तरह सत्ता में आई टीवीके के साथ नया मोर्चा बना लिया, उसके बाद द्रमुक का 'इंडिया' में साथ रहना वैसे भी मुश्किल था। इसी तरह, माकपा ने भी केरल में चुनाव के दौरान कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाया।मतभेद के मुद्दों पर संवाद और एक-दूसरे को समान स्तर पर अहमियत देना गठबंधन को मजबूत करने का एक रास्ता हो सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब इसके सभी सदस्य-दलों के भीतर सामूहिक भावना के साथ राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने की इच्छाशक्ति हो।जिस समय राजनीतिक चुनौतियां गहरा रही हों, वैसे में साझा मोर्चा मजबूत करने का रास्ता निकालने के लिए न्यूनतम बिंदुओं पर सहमति के रास्ते तैयार करने की जरूरत है। लोकतंत्र एक मजबूत विपक्ष के मुखर स्वर से ही जीवित रहता है। ऐसे में कुछ मतभेदों के बावजूद 'इंडिया' गठबंधन में शामिल दलों के बीच नए सिरे से मैदान में उतरने और हर दो महीने में बैठक करने पर बनी सहमति शायद वक्त का तकाजा भी है।

12 फरवरी 2019 को करोल बाग के अर्पित पैलेस होटल में लगी आग में 17 लोगों की जान गई। जांच में सामने आया कि होटल में अवैध निर्माण हुआ था और सुरक्षा उपकरण पर्याप्त नहीं थे। 2022 में मुंडका की व्यावसायिक इमारत में लगी आग में 27 लोगों की मौत हुई। वहां भी केवल एक निकास मार्ग था और सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी की गई थी। पिछले दिनों दिल्ली के मालवीय नगर स्थित हौजरानी क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि हमारे यहां हादसे अचानक नहीं होते बल्कि उन्हें पैदा किया जाता है।

बेगुनाह जिंदगियों से खेलता भ्रष्ट तंत्र और दिल्ली के अंतहीन अग्निकांड

(योगेश कुमार गोयल)

21 लोगों की दर्दनाक मौत, दर्जनों घायल, धुएं में घुटती सांसें, तीसरी मंजिल से जान बचाने के लिए छलांग लगाते लोग और बेसमेंट के बाहर बंद पड़ा निकास द्वार, यह केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक विफलता, भ्रष्ट व्यवस्था और नियमों की खुलेआम हत्या का भयावह परिणाम था। दुखद यह है कि यह कोई नई कहानी नहीं है। दिल्ली बार-बार अग्निकांडों में जलती है, लोग बार-बार मरते हैं, जांच समितियां बनती हैं, मुआवजे घोषित होते हैं और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। मालवीय नगर के हादसे में जो शुरुआती तथ्य सामने आए, वे किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने वाले थे। जिस भवन में 'लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट' और 'मिकासा होम्स' संचालित हो रहे थे, वहां कथित रूप से छह कमरों की अनुमति के बावजूद 25 से अधिक कमरे बनाए गए थे। भवन से निकलने का केवल एक रास्ता था। बेसमेंट में लोगों की मौजूदगी के बावजूद बाहरी गेट पर ताला लगा था। आग लगने के बाद धुआं इतनी तेजी से फैला कि लोग बाहर निकल ही नहीं सके। कुछ लोगों ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान बचाने की कोशिश की। यह दृश्य 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड की भयावह यादों को फिर से ताजा कर गया, जहां बाहर निकलने के रास्ते बंद होने के कारण 59 लोगों की मौत हो गई थी।

दिल्ली में अग्निकांडों का इतिहास बताता है कि हर बड़ी त्रासदी के पीछे कहानी लगभग एक जैसी है, अवैध निर्माण, सुरक्षा मानकों की अनदेखी, भ्रष्टाचार, फर्जी प्रमाणपत्र, बंद निकास द्वार और प्रशासनिक लापरवाही। 13 जून 1997 को हुए उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी, जो दिल्ली का अब तक का सबसे भयावह अग्निकांड माना जाता है। आग लगने के बाद सिनेमा हॉल में धुआं भर गया और निकास मार्ग अवरुद्ध होने के कारण लोग बाहर नहीं निकल सके। पूरे देश को झकझोर देने वाले इस हादसे के बाद सुरक्षा नियमों को सख्त बनाने की बातें तो बहुत हुईं लेकिन वास्तविकता यही है कि उनसे कोई स्थायी सबक नहीं लिया गया। 31 मई 1999 को लाल कुआं स्थित केमिकल गोदाम में लगी आग में 57 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद भी अवैध गोदामों और रासायनिक इकाइयों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लगाया गया। 8 दिसंबर 2019 को अनाज मंडी की अवैध फैक्टरी में लगी आग में 43 लोगों की मौत हुई। उस समय भी खुलासा हुआ था कि इमारत में निकास के पर्याप्त रास्ते नहीं थे, सीढ़ियां सामान से भरी थीं और खिड़कियों पर लोहे की ग्रिलें लगी थीं। जहरीले धुएं ने मजदूरों को सोते हुए ही मौत की नींद सुला दिया।

12 फरवरी 2019 को करोल बाग के अर्पित पैलेस होटल में लगी आग में 17 लोगों की जान गई। जांच में सामने आया कि होटल में अवैध निर्माण हुआ था और सुरक्षा उपकरण पर्याप्त नहीं थे। 2022 में मुंडका की व्यावसायिक इमारत में लगी आग में 27 लोगों की मौत हुई। वहां भी केवल एक निकास मार्ग था और सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी की गई थी। उसी वर्ष गोकुलपुरी की झुग्गी बस्ती में आग से 7 लोगों की जान चली गई। 2024 में अलीपुर की अवैध पेंट फैक्टरी में लगी आग में 11 लोगों की मौत हुई। 2026 में पालम और विवेक विहार में हुए अग्निकांडों में नौ-नौ लोगों की जान गई। अब मालवीय नगर की त्रासदी ने मृतकों की सूची में 21 और नाम जोड़ दिए हैं। दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2026 से 27 मई 2026 तक आग की घटनाओं में 45 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद विवेक विहार और मालवीय नगर की घटनाओं को जोड़ दें तो यह संख्या 67 से अधिक हो चुकी है। यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं बल्कि उन परिवारों की बर्बादी का दस्तावेज है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी इमारतें बन कैसे जाती हैं? कैसे आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां चलने लगती हैं? कैसे छह कमरों की अनुमति वाले भवन में 25 कमरे बन जाते हैं? कैसे फायर एनओसी के बिना होटल, रेस्टोरेंट और फैक्ट्रियां वर्षों तक संचालित होती रहती हैं? कैसे चार मंजिल की अनुमति वाले क्षेत्र में छह-सात मंजिलें खड़ी हो जाती हैं? इन सवालों का जवाब किसी जांच आयोग की मोटी रिपोर्ट में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की उस जड़ में छिपा है, जिसने पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया है। यदि कोई अवैध इमारत बनती है तो वह एक दिन में नहीं बनती। उसकी नींव पड़ती है, दीवारें उठती हैं, मंजिलें तैयार होती हैं, बिजली के कनेक्शन लगते हैं, पानी के कनेक्शन मिलते हैं और फिर व्यापार शुरू होता है। इस पूरी प्रक्रिया में अनेक सरकारी विभागों की आंखों के सामने सब कुछ होता है। इसलिए यह कहना कि प्रशासन को जानकारी नहीं थी, वास्तविकता से आंखें मूंदना होगा। सच यह है कि ऐसी अधिकांश इमारतें प्रशासन और कारोबारियों की मिलीभगत का परिणाम होती हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक घटनास्थल पर पहुंचते हैं। जांच के आदेश दिए जाते हैं, मुआवजे की घोषणाएं होती हैं और कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन क्या कभी किसी बड़े अधिकारी को कठोर दंड मिला? क्या कभी किसी विभागीय प्रमुख को जवाबदेह ठहराया गया? क्या कभी ऐसी कार्रवाई हुई कि भविष्य में कोई अधिकारी नियमों की अनदेखी करने का साहस न कर सके? दुर्भाग्य से जवाब है 'नहीं'। मालवीय नगर का हादसा भी केवल एक होटल या रेस्टोरेंट की कहानी नहीं है। यह उस पूरे शहरी विकास मॉडल पर प्रश्नचिह्न है, जहां मुनाफा मानव जीवन से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दिल्ली में हजारों ऐसी इमारतें हैं, जहां फायर सेफ्टी के उपकरण या तो हैं ही नहीं या केवल दिखावे के लिए लगाए गए हैं। अनेक भवनों में इमरजेंसी एग्जिट कागजों में मौजूद हैं लेकिन वास्तविकता में बंद पड़े हैं। कई जगहों पर बेसमेंट का उपयोग पार्किंग की बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। संकरी गलियों में बहुमंजिला भवन खड़े हैं, जहां दमकल की गाड़ियां तक नहीं पहुंच सकतीं।

अब समय आ गया है कि केवल जांच और मुआवजे की राजनीति से आगे बढ़ा जाए। दिल्ली में सभी होटलों, गेस्ट हाउसों, रेस्टोरेंटों, अस्पतालों, फैक्ट्रियों और बहुमंजिला इमारतों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। फायर एनओसी की व्यवस्था डिजिटल और पारदर्शी बने। अवैध निर्माण पर केवल जुर्माना नहीं बल्कि तत्काल ध्वस्तीकरण हो। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले भवन मालिकों और जिम्मेदार अधिकारियों पर गैर-इरादतन हत्या नहीं बल्कि कठोर आपराधिक मुकदमे दर्ज हों। जब तक जवाबदेही की तलवार ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, तब तक नीचे कोई नहीं सुधरेगा। मालवीय नगर की आग में मारे गए लोग किसी राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं थे, वे आम नागरिक थे, जिनमें महिलाएं थीं, विदेशी नागरिक थे, मरीजों के परिजन थे और बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर वहां ठहरे हुए लोग थे। आज जरूरत शोक व्यक्त करने से ज्यादा आत्ममंथन की है। उपहार कांड से लेकर मालवीय नगर तक लगभग तीन दशक बीत चुके हैं लेकिन व्यवस्था की मानसिकता नहीं बदली। यदि इस बार भी कुछ दिनों के शोर-शराबे के बाद सब कुछ सामान्य हो गया तो यकीन मानिए, अगला अग्निकांड केवल समय का प्रश्न होगा। तब फिर वही सवाल गूंजेगा कि आखिर बेगुनाह लोगों की जान से खेलते इस सिस्टम का जिम्मेदार कौन है? (लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और 'सागर से अंतरिक्ष तक- भारत की रक्षा क्रांति' सहित कई चर्चित पुस्तकों के लेखक हैं)(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

दहलीज़ लांघती बेटियां, स्कूल बैग से ज़्यादा भारी है सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ

(अतुल मौर्य)

भोर की पहली धूप के साथ जब लड़कियाँ घर की देहरी लाँघती हैं, तो उनके कंधों पर स्कूल बैग से कहीं अधिक भारी बोझ होता है। राजस्थान के एक छोटे कस्बे की प्रिया हो, या दिल्ली के किसी सरकारी विद्यालय की रोशनी; सुबह छह बजे उठकर, रसोई में चाय बनाकर, छोटे भाई-बहनों को तैयार करके जब वे बस की ओर दौड़ती हैं, तो यह दौड़ केवल विद्यालय तक नहीं होती। वे उस संसार में कदम रखती हैं जो उनसे कहता है- प्रश्न करो, आत्मविश्वास रखो, अपने सपनों को नाम दो।

कक्षाओं में वे संविधान की समता पढ़ती हैं, विज्ञान में तर्क के सूत्र सीखती हैं, भाषा में अपनी अभिव्यक्ति को धार देती हैं। परंतु संध्या की छाया के साथ जब वही लड़कियाँ घर की ओर लौटती हैं, तो वे एक बिल्कुल भिन्न दुनिया में प्रवेश करती हैं।

यह दुनिया किताबों की भाषा नहीं बोलती। यहां आवाज़ का तेज़ होना असंस्कार माना जाता है, हँसी की ऊँचाई मापी जाती है। एक ओर कक्षा में शिक्षिका कहती हैं- बेटा, बोलो, संकोच मत करो; दूसरी ओर घर में दादी टोकती हैं- इतनी ज़ोर से हँसते नहीं, लड़की हो। यही वह अदृश्य विभाजन रेखा है जिसे हम प्रायः दैनंदिन जीवन की सामान्यता मानकर अनदेखा कर जाते हैं।

स्वीकृति के भीतर की अदृश्य सीमा

समाज अब लड़कियों की पढ़ाई का उस तरह विरोध नहीं करता जैसा कभी करता था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -5) के अनुसार देश में 15-24 वर्ष की आयु की महिलाओं में साक्षरता दर 90 प्रतिशत तक पहुँच गई है यह निस्संदेह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। किंतु इस स्वीकार्यता की परतों के नीचे भी एक अदृश्य रेखा खिंची रहती है। मार्च 2025 में बिहार के दानापुर की खुशबू कुमारी की कहानी पूरे देश ने देखी, जिसने कक्षा 10 में 500 में से 399 अंक लाए, पर परिवार ने विज्ञान की जगह कला वर्ग में दाखिला दिलाया। खुशबू डॉक्टर बनना चाहती थीं।

यह कोई अपवाद नहीं है। (उच्च शिक्षा की अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट) 2022-23 के आँकड़े बताते हैं कि उच्च शिक्षा में लड़कियों का नामांकन अनुपात बढ़ा है, परंतु इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर विज्ञान में उनकी उपस्थिति अभी भी एक-तिहाई से कम है। शिक्षण, परिचर्या और मानविकी, ये क्षेत्र इसलिए सामाजिक रूप से मान्य हैं क्योंकि इनमें देखभाल और सेवा का भाव दिखता है और समाज स्त्री को इन्हीं भावों से जोड़कर देखने का आदी है।

अभियांत्रिकी, न्यायशास्त्र, राजनीति, रक्षा-सेवाएँ या वैज्ञानिक शोध जैसे क्षेत्रों में जाने वाली लड़कियाँ अभी भी सामाजिक कल्पनाशीलता की परिधि से बाहर हैं। जो इन क्षेत्रों की ओर जाती हैं, उन्हें प्रत्यक्ष प्रतिबंध से अधिक सूक्ष्म असहजताओं से गुजरना पड़ता है जैसे कि सेना में जाओगी, फिर शादी कौन करेगा? या वकालत में घर कब सँभालोगी? जैसे प्रश्न उनके सपनों को 'यथार्थ' की कसौटी पर बार-बार परखते हैं। धीरे-धीरे लड़की स्वयं भी यह आत्मसात करने लगती है कि उसके सपनों की एक 'सामाजिक सीमा' है। उसे आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है परंतु केवल उतनी, जितनी से स्थापित सामाजिक संरचना असहज न हो।

शिक्षाशास्त्री प्रो. कृष्ण कुमार की दृष्टि में समाज स्त्री को केवल विधि-निषेधों से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संकेतों की एक सूक्ष्म भाषा से गढ़ता है। पहनावा, चाल, आवाज़ का आरोह-अवरोह इत्यादि, ये सब मिलकर एक अघोषित पाठ्यक्रम रचते हैं। इसकी अभिव्यक्ति कभी-कभी बेहद ठोस होती है। दिल्ली के कुछ विश्वविद्यालयों में एक शोध के दौरान छात्राओं से पूछा गया कि वे कक्षा में प्रश्न पूछने से क्यों हिचकती हैं।

उत्तर चौंकाने वाले थे कि लड़के हँसते हैं, प्राध्यापक सीरियसली नहीं लेते, घर में माँ कहती हैं ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं। ये तीनों उत्तर तीन अलग-अलग दुनियाओं से आए थे परंतु एक ही निष्कर्ष पर मिलते थे - तुम्हारी आवाज़ का एक निर्धारित दायरा है। शायद इसीलिए बहुत-सी लड़कियाँ कम आयु में ही दो भिन्न संसारों के बीच एक अदृश्य सेतु बनाना सीख लेती हैं। विद्यालय में वे आत्मविश्वास से बोलती हैं, घर में संयम धारण करती हैं। वे जानती हैं कि किस परिसर में कितनी हँसी स्वीकार्य है, और कहाँ मौन ही समझदारी है। मनोविज्ञान इस प्रक्रिया को 'कोड-स्विचिंग' कहता है। कोड-स्विचिंग वह मानसिक श्रम है जो व्यक्ति को एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में जाते ही अपना व्यवहार, भाषा और अभिव्यक्ति बदलनी पड़ती है। यह श्रम अदृश्य है, थकाने वाला है, और अनिवार्यतः असमान क्योंकि यह लड़कियों से ही अपेक्षित है, लड़कों से नहीं।

नरेंद्र मोदी के 12 साल- भरोसे के हकीकत में बदलने का दौर

खैर यह सब होते हुए भी नरेन्द्र मोदी सरकार के सामने अभी चुनौतियां कम नहीं हैं। रोजगार सृजन, प्रति व्यक्ति आय में अंतर, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जल जीवन मिशन के बावजूद पेयजल की सहज उपलब्धता, खेती की बरसात पर निर्भरता, परिसीमन आदि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर ठोस काम किया जाना है।

यदि मॉर्निंग कंसल्ट की माने तो दुनिया के नेताओं की सूची पर एक नजर दौड़ाई जाएं तो केई भी वैश्विक नेता स्वीकार्यता में नरेन्द्र मोदी के आसपास भी नहीं टिकते।

(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा)

विपक्षी पार्टियां द्वारा लगातार देश और विदेश में अभियान चलाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रेंकिंग या स्वीकार्यता के मामलें में वैश्विक नेताओं से बहुत आगे हैं। 68 प्रतिशत स्वीकार्यता नरेन्द्र मोदी की है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्वीकार्यता रेंक लगातार नेगेटिव जा रही है। फालोवर्स में भी नरेन्द्र मोदी सबसे आगे हैं। दुनिया का संभवतः हमारा ही देश होगा जहां देश के बाहर भारत की छवि खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह स्वीकार्यता निश्चित रुप से भारत ही नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी उनकी लोकप्रियता और सर्वमान्यता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले चुनिंदा प्रधानमंत्री बन गए हैं। चुनिंदा इसलिए कि देश में पहले लोकसभा चुनाव 1952 में हुए पर पं. नेहरु 1947 से 1952 तक भी प्रधानमंत्री रहे। लगातार 12 साल कोई कम नहीं होते और वह भी लगातार 12 साल। सबसे बड़ी बात यह कि इस दौरान नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा ऐसे साहसिक निर्णय किये गये हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। माना तो यही जाता था कि कश्मीर में धारा 370 और 35 ए हटाना, राममंदिर का निर्माण, डिजिटल क्रांति, वैश्विक नेतृत्व, नोटबंदी, एक देश एक कर, घर घर शौचालय, घर घर कचरा संग्रहण, रक्षा उपकरणों का निर्यात, किसान सम्मान, मेक इन इंडिया, इंडिया फर्स्ट, बड़ी अर्थ व्यवस्था, तेजी से ढांचागत विकास, डिजिटल भुगतान, नक्सलवाद की नेस्तनाबूदी, आत्मनिर्भर भारत, परिवहन क्षेत्र में ढांचागत बदलाव आदि आदि समय समय पर की जाने वाली घोषणाएं केवल चुनाव जीतने के जुमले हैं पर लगभग असंभव माने जाने वाले यह काम आज धरातल पर उतरना सबसे बड़ी उपलब्धी मानी जा सकती है। इससे सबके साथ ही सबसे आश्चर्य जनक बात यह है कि लाख विरोध के बावजूद विपक्ष आज हाशिये में चला गया है।

कश्मीर से धारा 370 और 35 ए की समाप्ति हो चुकी है। दुनिया के किसी देश ने खुलकर इसका विरोध करने

की हिम्मत नहीं दिखाई। बाबरी मस्जिद के स्थान पर राममंदिर का निर्माण हो चुका है तो तीन तलाक, सीएए, यूसीसी और यहां तक कि सर्जीकल स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिन्दुर तक पर दुनिया के किसी देश की भारत के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हो पाई है। आज अर्थ व्यवस्था में जिस तेजी से बदलाव आया है और चौथी बड़ी अर्थ व्यवस्था बनने के बाद अब तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्था बनने की और तेजी से कदम बढ़ चुके हैं। जनधन योजना के समय जिस तरह से आलोचना का दौर चला था आज भुगतान में डिजिटलीकरण में इसकी बड़ी भूमिका तय हो चुकी है। जो लगभग असंभव माना जा सकता था वह आज डिजिटल भुगतान के माध्यम से संभव हो पाया है और पांच रु. के टमाटर का भुगतान भी सब्जीवाले तक को यूपीआई से आसानी से होने लगा है। सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना के भुगतान, पेंशन, अनुदान आदि आज सीधे खातों में जाने लगे हैं। यह किसी दिवा स्वप्न से कम नहीं है। आईपीसी सीपीसी में बदलाव किया जा चुका है। तो जीएसटी में लाख कमियां गिनाने के बावजूद आज समूचा देश एक देश एक कर के छाते के नीचे आ चुका है। बुनियादी ढांचें में तेजी से बदलाव आया है। आज वंदे भारत और नमो भारत ट्रेन चलने लगी है तो 33 किमी प्रतिदिन हाईवे का निर्माण हो रहा है। एक्सप्रेस हाईवे से आवागमन आसान हुआ है। आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लोगों को जोड़ा जा चुका है तो सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता का नेटवर्क विस्तारित किया गया है। आज 98 प्रतिशत घरों से घर घर कचरा संग्रहण होने लगा है तो अब घर घर में शोचालय बन चुके हैं। कोरोना के दौरान हमारे प्रयासों को सारी दुनिया द्वारा सराहा गया यहां तक कि कोरोना के दौरान जीवन रक्षक की भूमिका में भारत ने भूमिका निभाई। किसानों की आय में बढ़ोतरी के ठोस प्रयास हुए हैं तो किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को उनका आत्मसम्मान उपलब्ध कराया गया है। एमएसपी व्यवस्था में सुधार हुए हैं तो खेती किसानी के क्षेत्र में बदलाव छाप दिखाई दे रहा है। मेक इन इंडिया और इंडिया फर्स्ट भी आज साकार होता दिखाई दे रहा है। आज हम रक्षा उपकरणों का निर्यात करने लगे हैं तो सशस्त्रबलों के आधुनिकीकरण और निर्णय की स्वतंत्रता का परिणाम है कि आज सेनाएं आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रही है। आज देश आत्म निर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

जहां तक कूटनीतिक स्तर पर सफलता की बात है तो भारत आज पिछलग्गू देशों में नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लाख प्रयासों के बावजूद भारत के खिलाफ कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के पक्ष में आज तुर्कीया जैसे एकाध को छोड़कर कोई देश बोलने की स्थिति में नहीं है। मालदीव को नरेन्द्र मोदी के एक फोटो ट्वीट ने सबक सीखा दिया तो दूसरे देश भी भारत की ताकत को समझने लगे हैं।

खैर यह सब होते हुए भी नरेन्द्र मोदी सरकार के सामने अभी चुनौतियां कम नहीं हैं। रोजगार सृजन, प्रति व्यक्ति आय में अंतर, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जल जीवन मिशन के बावजूद पेयजल की सहज उपलब्धता, खेती की बरसात पर निर्भरता, परिसीमन आदि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर ठोस काम किया जाना है। देश में जिस तरह से पेपर लीक होने के मामले सामने आये हैं इससे युवाओं में निराशा हुई है उसे दूर करने की चुनौती सामने हैं तो स्टार्ट अप और कौशल विकास के बावजूद बेरोजगारी की दर अभी भी चिंतनीय स्तर पर है। साइबर क्राइम और गेमिंग जैसी नई चुनौतियां तो सोशल मीडिया के दुरुपयोग और अत्यधिक उपयोग के साइड इफेक्ट आदि अनेक समस्याएं समाधान चाहती है। देश आज तेजी से एक देष एक चुनाव के धरातल पर उतरने का इंतजार कर रहा है। रिन्यूवल एनर्जी पर बहुत कुछ हासिल करने के बावजूद अमेरिका ईरान युद्ध के कारण जिस तरह से तेल और एलपीजी का संकट आया है इसका भी दीर्घकालीन समाधान खोजा जाना है। हांलाकि समस्याएं अनवरत और नियमित प्रक्रिया है पर दीर्घकालीन योजनाओं से आसानी से निपटा जा सकता है।

इस सबके बावजूद देशवासियों को नरेन्द्र मोदी के प्रति पूरा भरोसा है। यही कारण है कि विपक्ष की लाख आलोचनाओं के बावजूद नरेन्द्र मोदी की स्वीकार्यता और भरोसे व उनके आत्मविश्वास में किसी तरह की कमी नहीं आई है। सौ टके की बात कही जाएं तो नरेन्द्र मोदी की अपार उपलब्धियों के बावजूद चुनौतियां भी अपार है और सबसे अच्छी बात यह कि देशवासियों का उनपर भरोसा भी पूरा है और वैश्विक स्वीकार्यता भी सबसे अधिक है। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

गोदावरी इस्पात प्रबंधन के खिलाफ भानुप्रतापपुर में फूटा ग्रामीणों का आक्रोश, अवैध पेड़ कटाई, प्रदूषण और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

स्थानीय लोकाधिकार समिति ने कलेक्टर को सौंपा अल्टीमेटम: 15 दिनों में जांच और कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन और चक्काजाम की चेतावनी

भानुप्रतापपुर। जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र में गोदावरी इस्पात आरोडेंगरी कच्चे प्रबंधन की गतिविधियों को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। 'स्थानीय लोकाधिकार समिति' के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को दो अलग-अलग विस्तृत शिकायत पत्र सौंपकर कंपनी पर पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाने, व्यापक स्तर पर अवैध वन कटाई करने, सीएसआर फंड में हेराफेरी करने और स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित रखने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर इन सभी मामलों पर निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो क्षेत्र की जनता उग्र आंदोलन और 'चक्काजाम' करने के लिए विवश होगी।

वृक्ष गणना में भारी विसंगतियां: 'खसरों की अवैध क्लबिंग' कर छुपाया गया वन घनत्व

कलेक्टर कार्यालय में दर्ज कराई गई पहली शिकायत आरोडेंगरी माइंस क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत परेकोडो तहसील दुर्गूकोंदल में वन एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा की गई वृक्ष गणना रिपोर्ट पर आधारित है, लोकाधिकार समिति के सदस्य हरेश चक्रधारी के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि लगभग 60.84 हेक्टेयर भूमि पर कंपनी को वेस्ट डंपिंग (कचरा फेंकने) की अनुमति देने के उद्देश्य से की गई वृक्ष गणना पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और फर्जी है। ग्रामीणों के अनुसार, प्रशासन के संयुक्त दल ने खसरा क्रमांक 188/1, 247/1 एवं 100 को एक साथ जोड़कर क्लबिंग करके वृक्ष गणना रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जबकि नियमतः प्रत्येक खसरे का क्षेत्रफल, भौगोलिक स्वरूप और वनस्पति घनत्व अलग-अलग है। ग्रामीणों का आरोप है कि संयुक्त गणना के पीछे असली मकसद उच्च वन घनत्व वाले क्षेत्रों को कम घनत्व वाला दर्शाना है ताकि वहां आसानी से माइनिंग कचरा डंप करने की अनुमति मिल सके। यह सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ' मामले में पारित ऐतिहासिक दिशानिर्देशों का खुला उल्लंघन है।

आंकड़ों का खेल: 2,000 से अधिक जीवित पेड़ों की गिनती गायब

जमीनी हकीकत का हवाला देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि संयुक्त दल की रिपोर्ट में केवल 11,984 वृक्षों की उपस्थिति दर्शाई गई है। लोकाधिकार समिति का दावा है कि इस सर्वे में भारी लापरवाही बरतते हुए सैकड़ों घने पेड़ों को गणना से जानबूझकर छोड़ दिया गया है। यदि इस संवेदनशील क्षेत्र की किसी निष्पक्ष और स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धति से दोबारा गणना कराई जाए, तो वर्तमान रिपोर्ट से कम से कम 2,000 से अधिक अतिरिक्त वृक्ष मिलेंगे। इतनी भारी संख्या में पेड़ों को रिकॉर्ड से गायब करना कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत को उजागर करता है।

पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संकट

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि भले ही उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में 'पहाड़ चट्टान' मद में दर्ज है, परंतु वास्तविक धरातल पर वहां समृद्ध वनस्पति मौजूद है। यदि इस क्षेत्र में माइनिंग का वेस्ट डंप किया जाता है, तो इसके नीचे स्थित कृषि भूमि, जल स्रोत और स्थानीय जैव विविधता पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। मिट्टी के कटाव (मृदा अपरदन) और भू-स्खलन का खतरा भी अत्यधिक बढ़ जाएगा, जिससे अंततः स्थानीय आदिवासियों की आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

खुले में डस्ट निपटान से नदियां हो रही हैं जहरीली

लोकाधिकार समिति द्वारा सौंपे गए दूसरे मांग पत्र में गोदावरी इस्पात प्रबंधन द्वारा फैलाए जा रहे भयंकर वायु और जल प्रदूषण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि आरोडेंगरी खदान से परिवहन के दौरान और माइंस से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल (डस्ट) को खुले आसमान के नीचे डंप किया जा रहा है। इसके कारण उड़ने वाली धूल और बारिश के दिनों में बहकर जाने वाला कचरा स्थानीय नदियों के पानी को अत्यधिक दूषित कर रहा है, जिससे जन-स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही खनन विस्तार की आड़ में वन कानूनों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर जंगलों की अवैध कटाई की जा रही है।

लोकाधिकार समिति द्वारा प्रशासन के समक्ष रखी गई मुख्य मांगें

त्रुटिपूर्ण वृक्ष गणना निरस्त हो: ग्राम पंचायत परेकोडो के तीनों खसरों की संयुक्त गणना रिपोर्ट तत्काल रद्द कर पृथक-पृथक वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए।

वेस्ट डंपिंग पर तत्काल रोक: जब तक निष्पक्ष सर्वेक्षण न हो, तब तक राजस्व भूमि पर कंपनी को किसी भी प्रकार के माइनिंग वेस्ट डालने की अनुमति न दी जाए।

स्थानीय युवाओं को अनिवार्य रोजगार: खदान प्रभावित क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत से गोदावरी इस्पात द्वारा कम से कम 150 स्थानीय बेरोजगार युवाओं को अनिवार्य नौकरी दी जाए।

सीएसआर एवं डीएमएफ फंड की जांच व ऑडिट: अब तक कागजों में दिखाए गए सीएसआर और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के कार्यों का भौतिक व आकस्मिक ऑडिट हो और घोटालेबाजों पर कड़ी कार्रवाई हो।

प्रभावित पंचायतों की सूची सार्वजनिक हो: खदान के प्रभाव क्षेत्र यानी 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के नामों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक की जाए।

प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम

शिकायत पत्र सौंपने के दौरान ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे लोकाधिकार समिति के पदाधिकारियों हरेश चक्रधारी, चंद्रमौली मिश्रा, रमल कोर्राम, संजू नेताम, जुगल कोरेटी, दिनेश कोरेटी, सुमन ध्रुव आदि ने कड़े शब्दों में कहा कि बस्तर एवं कांकेर क्षेत्र की जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना उनका संवैधानिक अधिकार है। इस ज्ञापन की प्रतिलिपियां अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भानुप्रतापपुर, खनि अधिकारी कांकेर, क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल और थाना प्रभारी भानुप्रतापपुर को भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रशासन आगामी 15 दिनों के भीतर इस विषय पर कोई उचित और ठोस कदम नहीं उठाता है, तो वे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की शरण में जाने के साथ-साथ क्षेत्र में उग्र जन-आंदोलन शुरू कर देंगे।

सड़कों और पुलों के निर्माण की धीमी गति पर बिफरे उप मुख्यमंत्री अरुण साव, 2 ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव द्वारा सड़कों व पुलों के निर्माण की धीमी गति पर गहरी नाराजगी जाहिर करने और ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश के बाद विभाग ने दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त कर दिए हैं। लोक निर्माण विभाग ने कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। वहीं पूर्व में दो ठेकेदारों को जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब का परीक्षण कर ठेकेदार के विरूद्ध कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मंगाया गया है। लोक निर्माण विभाग ने 10 जून को भी राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर केशलूर-जगदलपुर मार्ग में किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलवे लाइन के ऊपर केशलूर के पास बन रहे फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज में काम की प्रगति मंजूर किए गए निर्माण कार्यक्रम से काफी पीछे होने और तय किए गए माइलस्टोन्स के अनुरूप नहीं होने पर ठेकेदार मेसर्स अशोक कुमार मित्तल को

नोटिस जारी कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पिछले सप्ताह चार दिनों के बस्तर प्रवास के दौरान अपने चारों विभागों के कार्यों का निरीक्षण कर गहन समीक्षा की थी। उन्होंने निरीक्षण और बैठकों के दौरान सड़कों व पुलों के निर्माण की धीमी प्रगति पर अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर गहरी नाराजगी जताई थी। उन्होंने काम में लापरवाही, देरी और अनुबंध के अनुसार अपेक्षित तेजी नहीं लाने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने चार पुलों के निर्माण की धीमी प्रगति पर ठेकेदार मेसर्स गुप्ता कन्सट्रक्शन कंपनी का पंजीयन दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है। कंपनी द्वारा भवरडींग नदी पर अदनार-तोतर मार्ग, कोंडागांव के घोटिया-मुंडा-चांदाबेड़ा मार्ग और बड़े राजपुर विकासखंड के पलना-मरीगांव-कुंडई मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। कंपनी कबीरधाम जिले के बांटीपथरा से कुई (दमगढ़) मार्ग में हॉफनदी पर भी उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कर रही है। चारों कार्यस्थलों पर कंपनी का काम अपेक्षित गति से काफी पीछे है। विभाग ने कांकेर के आमाबेड़ा-सेमर गांव सड़क पर नेरूल नदी तथा बोड़ागांव-खासगांव-तरादुल मार्ग में डुमरीकेल नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के कार्य में लेट-लतीफी पर ठेकेदार निर्भय राम साहू का पंजीयन आगामी दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है। विभाग द्वारा प्रगति की लगातार समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने के लिए बार-बार निर्देशित और नोटिस जारी करने के बावजूद इन दोनों ठेकेदारों के काम की गति असंतोषजनक है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने नारायणपुर-सोनपुर-मरोदा मार्ग के चौड़ीकरण व सुधार कार्य की धीमी गति पर ठेकेदार पंकज हालदार को पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस के उत्तर का परीक्षण कर कार्रवाई के लिए बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मंगाया है। प्रमुख अभियंता ने सुकमा में पैकपारा-धनीकोड़ता मार्ग तथा केरलापाल-पटेलपारा-सिरसट्टी सड़क के कार्य में भी अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर ठेकेदार आशीष भदौरिया को पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब का परीक्षण कर कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मंगाया है। विभाग ने कांकेर-अमोड़ा-नरहरपुर मार्ग के ठेकेदार मेसर्स बी.एम.एस. प्रोजेक्ट, कोंडागांव में हडेली-कुदूर मार्ग के ठेकेदार मेसर्स सुराना एंड कंपनी और जगदलपुर-चित्रकोट मार्ग के ठेकेदार मेसर्स एस.के. अरोरा को कार्यों में धीमी प्रगति के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कार्यस्थलों पर काम की प्रगति मंजूर किए गए निर्माण कार्यक्रम से काफी पीछे होने और तय किए गए माइलस्टोन्स (महत्वपूर्ण पड़ावों) के अनुरूप नहीं होने पर सुकमा के चिंतलनार-मरियागुड़म सड़क के ठेकेदार के. मोहन रेड्डी, ट्रांससॉफ्ट इन्फ्रा और मेसर्स राघव कन्सट्रक्शन, कोंटा-गोलापल्ली मार्ग के ठेकेदार मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स राघव कन्सट्रक्शन तथा भेज्जी-चिंतागुफा सड़क का निर्माण कर रहे ठेकेदार के. मोहन रेड्डी एवं गोविन्द्र सिंह देशमुख को लोक निर्माण विभाग के सुकमा संभाग के कार्यपालन अभियंता द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सड़कों व पुलों के निर्माण में गुणवत्ता और समय-सीमा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी प्रकार की लेट-लतीफी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में बंद हुए सभी टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य, एक अक्टूबर तक जंगल सफारी पर रोक

रायपुर। मानसून के आगमन और वन्यजीवों के प्रजनन काल को देखते हुए, हर साल की तरह इस वर्ष भी देश के अधिकांश टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में जंगल सफारी 15 जून से 1 अक्टूबर तक साढ़े 3 महीने के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। पीसीसीएफएवं वन बल प्रमुख अरुण पांडेय ने बताया, हर साल मानसून के पहले टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों को बंद कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रकृति और वन्यजीवों की सुरक्षा तथा उनके प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) और वन्यजीव अभयारण्यों को पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मानसून के आगमन के साथ ही जंगलों में पर्यटन गतिविधियों पर यह अस्थायी रोक आगामी 1 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद वन्यप्राणी सप्ताह के अवसर पर 2 अक्टूबर से जंगल सफारी और अन्य पर्यटन गतिविधियां दोबारा शुरू की जाएंगी। वन विभाग के आला अधिकारियों के अनुसार, इस रोक के पीछे दो मुख्य कारण हैं। वर्षा ऋतु के दौरान जंगलों के भीतर स्थित कच्चे मार्ग और सफारी ट्रैक बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। लगातार बारिश से नदी-नालों में उफान और रास्तों में

कोंडागांव डोकरा हस्तशिल्प में महत्वपूर्ण योगदान है देवेंद्र का

कोंडागांव। भेलवांपदर पारा के सन् 1999 में मध्यप्रदेश के राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार विजेता व सन् 2003 में राज्य पुरस्कार विजेता तथा सन् 2006 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कालीदास सम्मान एवं सन् 2009 में राष्ट्रीय मेरिट सम्मान भारत सरकार द्वारा प्राप्त सिद्धहस्त डोकरा हस्तशिल्पि देवेंद्र मंडावी का महत्वपूर्ण योगदान है कोंडागांव डोकरा हस्तशिल्प को लोकप्रिय बनाने में। पेशे से वन विभाग कोंडागांव में लिपिक कार्यरत देवेंद्र शासकीय सेवक से पहले से ही सिद्धहस्त राज्य पुरस्कार विजेता है तथा इनका नाम नामचीन हस्तशिल्पियों में शुमार है। जनजाति समुदाय से संबंधित देवेंद्र की हस्तशिल्प साधना काफी लंबी है ; उतनी ही रोचक इनकी कला के क्षेत्र में संघर्ष यात्रा भी है। देवेंद्र बताते हैं कि राज्य पुरस्कार विजेता बनने के बाद से एक भी ऐसा अवसर नहीं चुका है, कि उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु अपनी प्रविष्टि ना सम्मिलित किया हो किंतु वे हार मानने वालों में से नहीं हैं। इस बार उन्होंने साठ किलोग्राम की वजनी कलाकृति राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता हेतु प्रविष्ट किया है। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण प्रतियोगिता जो कि कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में आयोजित किया गया है में उनकी कलाकृति चयनित हो गई है; अब अंतिम चयन प्रतियोगिता जो कि नई दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में होगी वहां पर चयन सुनिश्चित होना है। अपनी महीनों की अथक परिश्रम तथा कल्पनाशीलता से देवेंद्र ने अद्भुत हस्तशिल्प कारीगरी प्रस्तुत किया है। जो कि तथागत बुद्ध से प्रेरित है। उल्लेखनीय है कि इस बार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल (हस्तशिल्प) से छत्तीसगढ़ के पंद्रह में से 06 हस्तशिल्पि कोंडागांव जिला से चयन प्रक्रिया में सफलता प्राप्त किए हैं।

जैविक खेती से बढ़ेगी किसानों की आय, पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बल: मंत्री कश्यप

दंतेवाड़ा। किसानों और कृषि प्रेमियों को रासायनिक खादों व कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक और टिकाऊ खेती करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु आयोजित की गई है। दंतेवाड़ा जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय जैविक कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसानों, ग्रामीण युवाओं, महिला स्व-सहायता समूहों और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि दंतेवाड़ा जिले में जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं।

यहां की प्राकृतिक परिस्थितियां और किसानों की मेहनत जैविक कृषि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती केवल उत्पादन बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से भी जुड़ी है। जैविक खेती अपनाकर किसान भूमि की उर्वरता बनाए रखने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्यान्न उत्पादन कर सकते हैं। वन मंत्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार भी किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और कृषि विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने किसानों से खेतों की मेड़ों पर अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे भूमि संरक्षण, जल संवर्धन और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय विधायक चौतराम अटामी ने कहा कि जिले के किसान जैविक एवं प्राकृतिक खेती को अपनाकर बेहतर उत्पादन और अधिक आय प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को वैज्ञानिक जानकारी, प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराकर खेती को अधिक उन्नत एवं लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने किसानों से कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ लेने की अपील की। कार्यशाला के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने जैविक खेती, हरी खाद, जैव उर्वरक, वर्मी कम्पोस्ट, प्राकृतिक कीट एवं रोग प्रबंधन, मूल्य संवर्धन तथा जैविक उत्पादों के विपणन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी किसानों को दी। किसानों की समस्याओं का समाधान भी विशेषज्ञों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग तथा भूमगादी संस्था द्वारा स्टॉल लगाकर किसानों को विभिन्न योजनाओं, तकनीकों और कृषि नवाचारों की जानकारी दी गई। साथ ही कृषकों को कृषि आदान सामग्री एवं आम के पौधों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों द्वारा रागी से तैयार केक का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि ने केक काटकर महिला समूहों के प्रयासों की सराहना की और मूल्य संवर्धन आधारित गतिविधियों को ग्रामीण आजीविका का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।

नदियों के पुनरूद्धार एवं पुनर्जीवित करने संबंधी राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित राज्य की प्रमुख नदियों के पुनरूद्धार एवं पुनर्जीवित करने गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में प्रवाहित हो रही नदियों के पुर्नजीवन हेतु किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। नदियों का संरक्षण से जन स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में बैठक में जिलों के कलेक्टरों से नदियों के कैचमेंट एरिया में बनायी गई विविध जल संरक्षण एवं संचयन की कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा है कि हाईकोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार नदियों के पुनर्जीवित एवं पुनरूद्धार के कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों से नदियों के कैचमेंट एरिया में ऐसे जनउपयोगी कार्यों को लिया जाए जो भविष्य में नदियों के आस-पास रहने वाले लोगों की जरूरतों के अनुरूप हो। मुख्य सचिव ने नदियों के कैचमेंट एरिया में किए जाने वाले कार्यों से स्थानीय सरपंचों एवं जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से जोड़ने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा है कि जिले से उद्गम होने वाली नदियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी रखी जाए। जिससे नदियों के बारे में छात्रों को जानकारी मिले। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्कूलों के छात्र-छात्राओं का भ्रमण नदियों के उद्गम स्थल पर कराया जाए और नदियों की जानकारी के संबंध में छात्रों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। कलेक्टर ने नदियों के उद्गम स्थलों पर मेला उत्सव जैसे आयोजनों को करने के लिए भी कहा। बैठक में कलेक्टर रायगढ़, कोरबा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, सरगुजा, कोरिया, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, गरियाबंद और धमतरी के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिले में स्थित नदियों की वास्तविक स्थिति और संचालित कार्ययोजनाओं एवं परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टरों को नदियों के संरक्षण, संवर्धन के लिए जिला स्तरीय समितियों के संबंध में जानकारी दी।

सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में अंतर, रेगड़गट्टा में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे ग्रामीण

कोंटा। सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर किस तरह क्रियान्वयन हो रहा है, यह उनकी वास्तविक तस्वीर सामने लाता है। कोंटा विकासखंड के ग्राम पंचायत रेगड़गट्टा में ग्रामीणों ने योजनाओं के सही तरीके से संचालन और मूलभूत सुविधाओं को लेकर नाराजगी जताई है। कुल 130 घर और 750 की आबादी वाले इस पंचायत में ग्रामीणों का कहना है कि कई योजनाएं धरातल पर अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही हैं। नियमों के विपरीत और निम्न गुणवत्ता वाले कार्यों को लेकर ग्रामीणों में असंतोष बढ़ रहा है। उनका कहना है कि योजनाओं का उद्देश्य गांव का विकास और लोगों को सुविधा पहुंचाना है, लेकिन सही क्रियान्वयन नहीं होने से योजनाओं की उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

अप्रैल से खराब हैंडपंप, 600 मीटर दूर से ला रहे पानी

ग्रामीणों के अनुसार रेगड़गट्टा में अप्रैल माह से हैंडपंप खराब पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी कई बार जिम्मेदारों को दी गई, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं कराई गई। ग्रामीणों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें करीब 600 मीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। गांव में कुल तीन हैंडपंप खराब होने से पेयजल की समस्या और गंभीर हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या से सरपंच व सचिव को भी अवगत कराया गया, लेकिन समाधान नहीं होने के बाद अब उन्हें अपनी समस्या सामने लाने के लिए पत्रकारों का सहारा लेना पड़ रहा है।

तीन महीने से बिजली व्यवस्था ठप, ग्रामीणों में नाराजगी

ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के सरपंचपारा और पटेलपारा में पिछले तीन महीने से बिजली व्यवस्था बंद है। इस संबंध में कई बार सरपंच माड़वी जोगा को जानकारी दी गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग भी इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है। वहीं पंचायत के कुम्हारपारा में बिजली संचालित हो रही है, लेकिन सरपंच पारा और पटेलपारा के ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।

ग्रामीणों का आरोप, सचिव नहीं सुनते समस्याएं

ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत सचिव उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुनते हैं, जबकि गांव में कई मूलभूत समस्याएं लंबे समय से बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि खेती-किसानी के लिए डबरी, तालाब जैसे जल संरक्षण कार्यों की बहुत आवश्यकता है, लेकिन पंचायत सचिव के नियमित रूप से गांव में नहीं आने और ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देने के कारण उनकी मांगें पूरा नहीं हो पा रही हैं।

नल जल योजना पर भी उठे सवाल

ग्रामीणों ने नल जल योजना को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि गांव में घर-घर नल तो लगा दिए गए है, लेकिन अभी तक घरों तक पानी नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाना ही नहीं है तो ऐसी योजनाओं का निर्माण केवल दिखावे के लिए क्यों किया जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि खराब हैंडपंप, बिजली व्यवस्था और नल जल योजना जैसी मूलभूत समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ गांव के लोगों तक पहुंच सके।

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु कलादलों से 18 जून तक आवेदन आमंत्रित

बिलासपुर। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में जनजागरूकता गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए कलादलों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके लिए पात्र एवं पंजीकृत कलादल/कला मंडलियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा जारी सूचना के अनुसार ऐसे कलादल एवं कला मंडलियां, जो गीत एवं नाट्य विभाग भारत सरकार, जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ संवाद, सूचना प्रसारण अथवा संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन में पंजीकृत हों, चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कलादल प्रशिक्षण कार्यक्रम, लखनऊ से प्रशिक्षण प्राप्त कलादलों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इच्छुक आवेदक अपने आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित 18 जून 2026 को सायं 5 बजे तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, नूतन चौक, सरकंडा, बिलासपुर में जमा कर सकते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कलादलों की सहभागिता से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे आमजन को एचआईवी/एड्स की रोकथाम, उपचार एवं बचाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी सरल और प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराई जा सकेगी। जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम ने पात्र कलादलों से निर्धारित समयावधि में आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है।

एक हेलमेट, अनेक जीवन सुरक्षित रू सड़क सुरक्षा के लिए प्रशासन की पहल

बिलासपुर। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा हेलमेट उपयोग को बढ़ावा देने की पहल की गई है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने जिले के सभी विभाग प्रमुखों को पत्र जारी कर दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने को अनिवार्य रूप से प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाएं केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती हैं। जिले में पिछले वर्ष लगभग 300 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई थी। इनमें कई ऐसे मामले भी सामने आए, जिन्हें यातायात नियमों के पालन और सुरक्षा उपाय अपनाकर टाला जा सकता था। मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हेलमेट दुर्घटना के दौरान सिर को गंभीर चोटों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मृत्यु की आशंका को काफी हद तक कम करता है। इसी उद्देश्य से सभी कार्यालयों में हेलमेट उपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों से कहा है कि वे अपने कार्यालयों में आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति छोटी-सी जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव अनेक परिवारों को दुर्घटनाओं की पीड़ा से बचा सकता है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं हेलमेट पहनें और अपने परिवार व परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करें। सुरक्षित यात्रा और जिम्मेदार नागरिकता का यह संकल्प सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

5 जून तक करें आवेदनः मस्तूरी जनपद पंचायत में 7 जलाशयों के मत्स्य पालन पट्टों के लिए आमंत्रित किए गए आवेदन

बिलासपुर। जनपद पंचायत मस्तूरी द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय मत्स्य समूहों एवं युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद क्षेत्र के विभिन्न जलाशयों एवं तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन किया जा रहा है। इच्छुक पात्र आवेदकों से 25 जून 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जनपद पंचायत मस्तूरी द्वारा जारी सूचना के अनुसार रामअवतार, फूटहा मुड़ा, बंधवा, जेतपुरी, सेमराडीह, मोंगरा एवं चिरसा जलाशयों का पट्टा मत्स्य पालन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रदान किया जाएगा। पट्टा आवंटन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ आदर्श मत्स्य पालन नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुरूप संपादित की जाएगी।निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों, मछुआ समूहों, महिला स्व-सहायता समूहों, मत्स्य कृषकों तथा मत्स्य पालन में प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में संबंधित वर्ग के पंजीकृत समूहों एवं समितियों को भी नियमानुसार प्राथमिकता का लाभ मिलेगा। जनपद पंचायत ने इच्छुक आवेदकों से समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। इस पहल से क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ ग्रामीणों की आय में वृद्धि एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। जनपद पंचायत मस्तूरी ने पात्र हितग्राहियों, समितियों एवं स्व-सहायता समूहों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए 25 जून 2026 तक अपना आवेदन जमा करें।

कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं

कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

बिलासपुर। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने उनसे मिलकर निजी एवं सामुदायिक शिकायत संबंधी आवेदन दिया। उन्होंने अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे एवं जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल ने भी लोगों की समस्याएं सुनी।जनदर्शन में तखतपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मोछ के जनपद सदस्य रामकुमार सिंगरौल ने ग्राम जोरापारा को नया राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग उठाई। आवेदन में बताया गया कि जोरापारा की आबादी लगभग 1800 है। राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने से विकासखण्ड मस्तुरी के ग्राम लिमतरा निवासी मुरलीधर पटेल ने अपने पोल्ट्री फार्म पर तूफान से गिरे सागौन के पेड़ों के कारण हुए नुकसान की शिकायत संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि 15 मई को आए तेज तूफान में चार सागौन के पेड़ पोल्ट्री फार्म पर गिर गए, जिससे पोल्ट्री फार्म पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने नुकसान का सर्वे कराकर पेड़ों को हटाने एवं लकड़ियों का उपयोग करने की अनुमति देने की मांग की। तखतपुर के सेमरा के ग्रामीण राजेंद्र जायसवाल ने कलेक्टर से मुलाकात कर प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरे किस्त की राशि दिलाने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पहले किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। दूसरे किस्त की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उनके मकान का कार्य अपूर्ण है। जनदर्शन में बिजली विभाग से जुड़ी समस्या भी सामने आई। ग्राम मटियारी निवासी किसान रामकिशुन सूर्यवंशी ने कहा कि विगत 8 वर्ष पूर्व अपने कृषि भूमि में ट्रांसफार्मर एवं बिजली पोल लगाने के लिए राशि जमा करने के

बावजूद अब तक उनके खेत तक पोल नहीं लगाए गए हैं, जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने शीघ्र विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। इसी तरह जोरापारा निवासी छात्रा रिंकी ने छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत की। उसने बताया कि कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद पात्र होने के बावजूद अब तक उसे छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाया है। छात्रा ने जनदर्शन के माध्यम से छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने की मांग की। बेलतरा तहसील के ग्राम लिम्हा निवासी रेशमदास मानिकपुरी ने अपनी कृषि भूमि के सीमांकन में हो रही देरी की शिकायत की। उन्होंने बताया कि मार्च 2026 में आवश्यक शुल्क जमा करने के बावजूद अब तक सीमांकन की कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने शीघ्र सीमांकन कराने और उचित कार्यवाही करने की मांग की है। जनदर्शन में शहर के मिनीमाता नगर, तालापारा निवासी रविंद्र कुमार खुंटे ने आगजनी की घटना में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक सहायता राशि दिलाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि नवंबर 2025 में उनके घर में आग लगने से घरेलू सामान और आवश्यक वस्तुएं जलकर नष्ट हो गई थीं। आवेदन के माध्यम से उन्होंने शीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की। इसके अलावा बापू उप नगर निवासी दिव्यांग महिला सत्रो ने शासकीय योजना के तहत प्राप्त आबंटित आवास का स्थान परिवर्तन कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि शारीरिक दिव्यांगता के कारण दूर स्थित आवास में रह पाना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें हेमूनगर क्षेत्र में स्थित आवास उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज, 21 जून को बहतराई स्टेडियम में होगा जिला स्तरीय भव्य आयोजन

बिलासपुर। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 2026 को बिलासपुर के बी.आर. यादव स्मृति राज्य स्तरीय खेल परिसर, बहतराई इंडोर स्टेडियम में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष का विषय योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखा गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः 7 बजे से सामूहिक योगाभ्यास एवं विभिन्न योग आसनों का प्रदर्शन किया जाएगा। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में कार्यक्रम की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। आयोजन की व्यापकता को देखते हुए विभिन्न विभागों को आवश्यक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, उद्यानिकी विभाग, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा आयुष विभाग सहित अन्य विभाग समन्वित रूप से

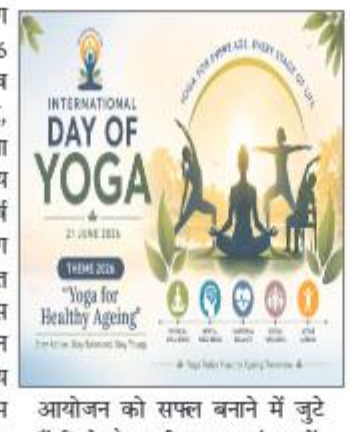

आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं।जिले के सभी जनपद पंचायतों, नगरीय निकायों तथा शैक्षणिक संस्थानों में भी योग दिवस के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। योग दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पौधरोपण, बीज वितरण, स्वच्छता अभियान एवं पर्यावरण जागरूकता गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थियों, स्काउट-गाइड, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) तथा अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।आयोजन स्थल पर प्रतिभागियों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सकों एवं चिकित्सा दलों की तैनाती की जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान की जा सके।योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा के लिए 16 जून को कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं जिले में योग के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश जन-जन तक पहुंचाने की अपील की है।

वीबी जीराम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर सीईओ संदीप का जोर

- संभाग स्तरीय प्रशिक्षण में अधिकारियों को दिया गया विस्तृत मार्गदर्शन

बिलासपुर। भारत सरकार एवं राज्य कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार वीबी जीराम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायत बिलासपुर के सभागार में संभाग स्तरीय दो दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल ने वीबी जीराम जी योजना के उद्देश्यों, महत्व एवं क्रियान्वयन की रूपरेखा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है, जब मैदानी स्तर पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी उसकी अवधारणा, प्रक्रियाओं और अपेक्षित परिणामों से भलीभांति परिचित हों। उन्होंने अधिकारियों से प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक कार्यों में लागू करते हुए योजना को सफल बनाने का आह्वान किया। प्रशिक्षण के दौरान भारत सरकार एवं राज्य कार्यालय से प्राप्त प्रेजेंटेशन एवं दिशा-निर्देशों के आधार पर प्रतिभागियों को योजना के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में वीबी जीराम जी योजना के उद्देश्यों, क्रियान्वयन प्रक्रिया, निगरानी तंत्र तथा मैदानी स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तार से मार्गदर्शन प्रदान किया गया। राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के रूप में बिलासपुर की सहायक परियोजना अधिकारी (मनरेगा) श्रीमती अनुराधा शुक्ला सहित संभाग के सभी सहायक परियोजना अधिकारियों ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

जल स्तर बढ़ने पर मिनीमाता बांध से छोड़ा जाएगा पानी...

जल संसाधन विभाग ने जारी किया अलर्ट

बिलासपुर। आगामी वर्षाकाल के दौरान आवश्यकता होने पर मिनीमाता बांगो बांध माचाडोली एवं हसदेव बराज दर्री से नदी में जल प्रवाहित किया जाएगा। सर्वसाधारण एवं कार्य एजेंसियों को सूचित किया जाता है कि बांध से नीचे, हसदेव नदी के किनारे, बाढ़ क्षेत्र में स्थापित चल-अचल संपत्ति सुरक्षित स्थानों पर ले जावें। बाढ़ क्षेत्र में स्थापित खनिज खदान, ठेकेदार, औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों आदि को भी सूचित किया जाता है कि वह अपनी परिसंपत्तियों को बाढ़ क्षेत्र से बाहर कर लेवें। अकस्मात बाढ़ से होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जल संसाधन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।बाढ़ क्षेत्रों में आने वाले संभावित ग्रामों में बांगो, लेपरा, नुनिया, कछार, कोनकोना, पोड़ीउपरोड़ा, चर्रा, पाराघाट, छिनमेर, सिरकीकला, केरा, पाथा, सिलियारीपारा, तिलसाभाटा, हथमार, छिर्रापारा, डग्गुपारा, करमीपारा, जुनापारा, लोरीडांड, टुंगमुड़ा, तिलाईडांड, नवागांव, झोरा, कौराघाट, पोड़ीखोहा, डोंगाघाट, धनगांव, लोटलोटा, नर्मदा, औराकछार, झाबू, सोनगुड़ा, नवागांव, स्याहीमुड़ी, जेलगांव, चारपारा, खैराभावना, बलरामपुर, भलपहरी, जोगीपाली, कोहड़िया, रातारवार, गेवराघाट, इमलीडुग्गू, कुदुरमाल, बरीडीह, मोहरा, देवरी, चिचोली, कटबितला, झीका, ढिठोली, सहित अन्य गांव शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष सेवा,सुशासन और विकास को समर्पित :उपमुख्यमंत्री अरुण साव

बिलासपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर देश में हुए विकास, सुशासन और जनकल्याणकारी उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से शुरू हुई यह यात्रा जनता के विश्वास, पारदर्शी शासन और गरीब कल्याण के संकल्प पर आधारित रही है, जिसके कारण प्रधानमंत्री श्री मोदी को लगातार तीसरी बार देश की सेवा का अवसर मिला है। इस अवसर पर विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी ,महापौर श्रीमती पूजा विधानी, श्री दीपक ठाकुर एवं श्रीमती हर्षिता पांडे भी उपस्थित थीं। श्री साव ने कहा कि केंद्र सरकार ने जन-धन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया

है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए सरकारी सहायता सीधे हितग्राहियों तक पहुंची है तथा पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिला है। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में देश में सड़क, रेल, मेट्रो, हवाई अड्डों और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों को लाभ मिला है, वहीं रेलवे के विद्युतीकरण और वंदे भारत ट्रेनों ने आधुनिक परिवहन व्यवस्था को नई गति दी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विकास के साथ-साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय गौरव और जनभागीदारी को भी सशक्त किया है। वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तथा जी-20 की सफल अध्यक्षता, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और बढ़ते विदेशी निवेश ने विश्व समुदाय के भारत पर बढ़ते विश्वास को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में विकसित, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के निर्माण का अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है तथा केंद्र सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

सीएम हेल्पलाइन के आवेदक से कलेक्टर ने की सीधी बात,दिया समाधान का भरोसा.....

- समस्याओं के त्वरित निराकरण के अधिकारियों को दिए निर्देश
- स्कूल प्रवेश उत्सव, खाद-बीज वितरण, सुशासन तिहार, अरपा पुनर्जीवन एवं राजस्व प्रकरणों की समीक्षा

बिलासपुर। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, पीएमओ पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, सीजी ग्रिवांस, मुख्यमंत्री घोषणाओं तथा शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल सहित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान कलेक्टर श्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए बिरकोना निवासी श्री राजेंद्र साहू से स्वयं फोन पर चर्चा की। जब कलेक्टर ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं कलेक्टर बिलासपुर बोल रहा हूं, तो श्री साहू को एक बार विश्वास नहीं हुआ। कलेक्टर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए उनकी शिकायत की जानकारी ली। श्री साहू ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिए गए आवेदन पर कार्रवाई की जानकारी चाही थी। कलेक्टर ने बताया कि योजना का पोर्टल वर्तमान में बंद है तथा पोर्टल प्रारंभ होते ही नियमानुसार कार्रवाई कर उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाएगा। इस पर

आवेदक ने संतोष व्यक्त किया। कलेक्टर ने आगामी स्कूल प्रवेश उत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विद्यालयों में उत्साहपूर्वक प्रवेश उत्सव आयोजित किया जाए तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने जर्जर भवनों में बच्चों की पढ़ाई नहीं कराने, न्योता भोज आयोजित करने तथा शैक्षणिक गुणवत्ता और परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के बीच समसामयिक विषयों पर नियमित चर्चा हो तथा आरटीई के तहत प्रवेश प्राप्त बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। स्कूली बसों की जांच तथा निजी विद्यालयों में शासन के नियमों के पालन पर भी विशेष जोर दिया गया। खाद एवं बीज वितरण की समीक्षा में बताया गया कि जिले में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 2 हजार मीट्रिक टन अधिक उर्वरक का वितरण किया गया है। कलेक्टर ने समितिवार उपलब्धता की जानकारी लेते हुए परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में अरपा नदी के पुनर्जीवन एवं समन्वित विकास पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने नदी किनारों पर व्यापक पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण तथा नदी के प्राकृतिक स्वरूप को पुनर्स्थापित करने के लिए योजनाबद्ध कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अरपा नदी को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं, जिन पर गंभीरता से कार्य किया जाना चाहिए।

जिला खेल परिसर में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 24 को....

बिलासपुर। शासकीय नवीन पिछड़ा वर्ग बालक क्रीड़ा परिसर में वर्ष 2026-27 में प्रवेश के लिए खिलाड़ियों के चयन हेतु प्रवेश परीक्षा 24 जून 2026 को सवेरे 8 बजे से स्व. बीआर यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में आयोजित की जाएगी। चयन सूची 27 जून 2026 को जारी करने के पश्चात प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी। खेल परिसर में एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी एवं स्विमिंग विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष कुल 35 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। प्रवेश के लिए आवेदक की आयु 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में 14 वर्ष से कम हो वे सब जूनियर वर्ग में एवं 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक वरिष्ठ वर्ग से क्रीड़ा परिसर की चयन परीक्षा में शामिल हो सकते है। इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न शारीरिक दक्षता एवं खेल परीक्षणों से गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया में 50 मीटर एवं 100 मीटर दौड़, ऊँची कूद, शटल रेस (4म10 मी.), स्टैंडिंग ब्राड जंप, गतिशील स्फूर्ति परीक्षण, अपर बॉडी बेंडिंग, पुश अप, लेग रेसिंग, सिट-अप एवं 400 मीटर एवं 800 मीटर दौड़ शामिल हैं। चयनित खिलाड़ियों के लिए नवीन पिछड़ा वर्ग बालक खेल परिसर, बिलासपुर में निःशुल्क आवास, भोजन, खेल प्रशिक्षण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई स्थित मैदान, जिला खेल परिसर स्थित मैदान एवं स्विमिंग पूल का उपयोग किया जाएगा।

धूप-दीप, कपूर से दूर होती है नकारात्मक ऊर्जा

धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार घर में सुगंध, धूप और कपूर का प्रयोग केवल वातावरण को महकाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका संबंध सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और ग्रहों की शुभता से भी माना गया है। सनातन परंपरा में पूजा-पाठ के समय धूप, दीप और कपूर जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि इससे घर का वातावरण पवित्र होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और नवग्रहों का शुभ प्रभाव बढ़ता है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में भी सुगंधित वातावरण को सुख-समृद्धि का कारक माना गया है।

कपूर जलाने से दूर होती है नकारात्मकता

धार्मिक मान्यता के अनुसार सुबह और शाम कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। कपूर का संबंध विशेष रूप से राहु और केतु ग्रह से माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यदि घर में बार-बार तनाव, डर, बेचैनी या बिना कारण बाधाएं उत्पन्न हो रही हों तो कपूर जलाना लाभकारी माना जाता है। पूजा के बाद कपूर की आरती करने से वातावरण शुद्ध होता है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी घर के कोनों में कपूर की सुगंध फैलाने से रुकी हुई ऊर्जा सक्रिय होती है और मानसिक शांति बनी रहती है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि और शांति का वास होता है।

धूप और धूपबत्ती का धार्मिक महत्व

पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में धूप को देवताओं को प्रसन्न करने वाला बताया गया है। मान्यता है कि चंदन, गुग्गुल, लोबान या प्राकृतिक धूप जलाने से देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुगंधित धूप का संबंध गुरु और शुक्र ग्रह से माना जाता है। इससे घर में सकारात्मकता, आनंद और वैभव बढ़ता है। घर में नियमित रूप से धूप जलाने से वातावरण की अशुद्धियां दूर होती हैं और मन पूजा-पाठ में लगता है। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और मधुरता बनी रहती है।

सुगंधित वातावरण से बढ़ती है सकारात्मक ऊर्जा

धार्मिक मान्यता है कि जिस घर में स्वच्छता और सुगंध बनी रहती है वहां मां लक्ष्मी का निवास होता है। फूलों की सुगंध, इत्र या प्राकृतिक सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करने से मन शांत रहता है और घर में प्रसन्नता का वातावरण बनता है।

ज्योतिष के अनुसार सुगंध का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है। शुक्र ग्रह को सुख, सौंदर्य और ऐश्वर्य का कारक कहा जाता है। इसलिए घर में सुगंधित वातावरण बनाए रखने से शुक्र मजबूत होता है और जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ती हैं।

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा में हमेशा प्राकृतिक कपूर, शुद्ध घी और प्राकृतिक धूप का ही प्रयोग करना शुभ माना जाता है। टूटे या गंदे पात्र में धूप या कपूर नहीं जलाना चाहिए। सुबह और शाम पूजा के समय धूप-दीप करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और ग्रहों की शुभता बढ़ती है।

गर्दन के जिद्दी कालेपन हटाने के नुस्खे

कुछ लोगों की गर्दन का रंग त्वचा के बाकी हिस्सों से ज्यादा काला होता है, जिसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। पर इसका सोल्यूशन लोगों को एक ही समझ में आता है स्क्रबिंग। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर गर्दन के कालेपन की वजह कोई शारीरिक समस्या नहीं है तो इसे घर पर ही कुछ तरीकों से दूर किया जा सकता है। गर्दन के कालेपन को दूर करने के लिए यहां बताए घरेलू नुस्खे आजमाए जा सकते हैं:

संतरे के छिलके

संतरे के छिलके में ऐसे एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो त्वचा के रंग को काले करने के लिए जिम्मेदार टायरोसिन नामक अमीनो एसिड के खिलाफ लड़ते हैं।

कैसे करें इस्तेमाल?

संतरे के छिलकों को सुखाकर उसका पाउडर बना लें और उसके बाद उसे दूध में मिक्स करके त्वचा पर अप्लाई करें। यह तरीका लगातार अपनाने से असर देखने को मिल सकता है।

सेब का सिरका

सेब के सिरके में मैलिक एसिड होता है, यह स्किन के pH लेवल को बैलेंस करने और डेड स्किन को हटकर नैचुरल ग्लो लाने में मदद करता है।

कैसे करें इस्तेमाल?

दो बड़े चम्मच सेब के सिरके में दो चम्मच पानी मिलाकर रूई से गर्दन पर लगाएं। फिर सादे पानी से धो लें।

आलू का रस

आलू के रस में मौजूद गुण त्वचा का रंग हल्का करने में बड़े मददगार हैं। आलू का रस डार्क पैच को भी हटाने का काम करता है।

कैसे करें इस्तेमाल?

एक छोटे आलू का रस निकालकर उसे गर्दन पर सीधे अप्लाई करें और हल्के हाथ से मसाज करें। इसे लगाने के बाद सूख जाने दें और उसके बाद ही पानी से धोएं।

सिर में दर्द बने रहने पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी

सिरदर्द की समस्या वैसे तो बहुत आम है। ये हर व्यक्ति को कभी न कभी जरूर होती है, लेकिन जब आपको बार-बार सिर में दर्द होने लगे, तो यह सिर्फ थकान का संकेत नहीं बल्कि शरीर की किसी अंदरूनी समस्या का इशारा भी हो सकता है। तनाव, नींद की कमी, तो कभी डिहाइड्रेशन या माइग्रेन इसके पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं। कई लोग पेन किलर दवाएं लेकर राहत तो पा लेते हैं, लेकिन वास्तविक कारण को नजरअंदाज कर देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बार-बार होने वाला सिरदर्द जीवनशैली, खान-पान, हार्मोनल बदलाव या कुछ चिकित्सीय स्थितियों से जुड़ा हो सकता है। यदि सिरदर्द लगातार बना रहे या बहुत गंभीर हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

स्ट्रेस से लेकर नींद की कमी तक हो सकता है कारण

बार-बार सिर में दर्द होने की समस्या के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। तनाव इसका सबसे आम कारण है। मेंटल स्ट्रेस और चिंता मांसपेशियों में खिंचाव पैदा कर सकते हैं, जिससे टेंशन हेडेक होता है। यह सिर के दोनों तरफ दबाव जैसा महसूस हो सकता है। इसके अलावा नींद की गुणवत्ता में कमी भी सिरदर्द बढ़ा सकती है। रोजाना 7-9 घंटे की अच्छी नींद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर आपकी नींद लगातार पूरी नहीं हो रही है तो इसके कारण भी सिरदर्द हो सकता है।

कहीं आपको माइग्रेन तो नहीं?

माइग्रेन के शिकार लोगों के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसे डॉक्टर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर मानते हैं। माइग्रेन में सिर के एक हिस्से में धड़कन जैसा दर्द, मितली और रोशनी से परेशानी हो सकती है। इसके साथ कुछ लोगों को उल्टी-मितली जैसा भी लगता रहता है। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, इसलिए समय रहते इसका उपचार किया जाना जरूरी है। कई बार मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी माइग्रेन हो सकता है।

बार-बार होता है सिरदर्द तो क्या करें?

सिरदर्द में कई आसान उपायों की मदद से काफी हद तक आराम पाया जा सकता है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने या नंबर का चश्मा न लगाने से आंखों पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे सिरदर्द हो सकता है। ऐसे में अपना स्क्रीन टाइम कम करें। लंबे समय तक भूखे रहने से ब्लड शुगर का लो हो सकता है, जो सिरदर्द को ट्रिगर कर सकता है। थोड़ी-थोड़ी देर पर कुछ खाते रहें। बहुत ज्यादा चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक लेने से सिरदर्द हो सकता है। कैफीन वाली चीजों का सेवन कम करें।

आज का राशिफल

मेष राशि - करियर में आपके साहस और मेहनत की प्रशंसा होगी, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। बिजनेस में नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे। लव लाइफ में साथी के साथ रिश्ता और भी अधिक गहरा होगा और आप एक-दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहेगा और आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। कल का दिन नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है।

वृषभ राशि - धन संबंधी मामलों में बहुत सतर्क रहें और सोच-समझकर ही पैसा खर्च करें। बिजनेस में किसी को भी बिना जांच-परख के उधार न दें। लव लाइफ में वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपके गलत शब्द रिश्ते में खटास पैदा कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से गले या आंखों का ध्यान रखें। कल आपको अपने निवेशों की समीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है। धैर्य से काम लें और अपनी योजनाओं में कोई बड़ा बदलाव न करें।

मिथुन राशि - बिजनेस में लाभ के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। लव लाइफ में साथी के साथ रोमांटिक पल व्यतीत करेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप मन से भी काफी प्रसन्न रहेंगे। कल आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे, उसे समय पर और बेहतर ढंग से पूरा कर लेंगे। सामाजिक कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे।

कर्क राशि - काम का दबाव हो सकता है और किसी अनचाहे खर्च का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में सावधानी बरतें और किसी पर भी बिना सोचे-समझे भरोसा न करें। लव लाइफ में साथी के साथ थोड़ी दूरियां महसूस हो सकती हैं, इसलिए बातचीत जारी रखें। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाही न करें और पर्याप्त आराम लें। कल व्यर्थ की भागदौड़ से बचें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं।

सिंह राशि - कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बिजनेस में अचानक धन लाभ होने के प्रबल योग हैं। लव लाइफ में साथी के साथ बेहतरीन समय व्यतीत करेंगे और आप भविष्य की सुखद योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप मानसिक रूप से काफी प्रसन्न महसूस करेंगे। कल आप जो भी कार्य शुरू करेंगे, उसमें सफलता की पूरी संभावना है।

कन्या राशि - आपको कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपके पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बिजनेस में नई योजनाएं सफल होंगी और व्यापारिक सौदों में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लव लाइफ में साथी के साथ तालमेल बहुत ही सुंदर रहेगा और आपसी प्रेम और गहरा होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा है, ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा। कल कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान एक कुशल रणनीतिकार के रूप में बनेगी।

तुला राशि-तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। बिजनेस में कोई बड़ा सौदा फाइनल हो सकता है, जो भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा। लव लाइफ में साथी के साथ आपका रिश्ता और भी गहरा होगा। स्वास्थ्य के प्रति आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे, ऊर्जा का संचार बना रहेगा। कल आप किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में रुचि ले सकते हैं। आपका मन शांत रहेगा, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे।

वृश्चिक राशि -सहकर्मियों से सतर्क रहें और फालतू की बातों में समय न गंवाएं। बिजनेस में अभी किसी भी प्रकार के बड़े निवेश को टालना ही बेहतर होगा। लव लाइफ में साथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, उनका ध्यान रखें। स्वास्थ्य में पेट या पाचन से जुड़ी समस्याओं के प्रति सचेत रहें और हल्का भोजन लें। कल आपको धैर्य रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। शांत रहकर ही आप मुश्किलों को पार कर पाएंगे।

धनु राशि- अपने प्रतिस्पर्धियों पर नजर रखें और योजनाबद्ध तरीके से काम करें। लव लाइफ में साथी के साथ रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी और आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य है, बस नियमित खान-पान का ध्यान रखें। कल आप अपने कार्यों के प्रति काफी सजग रहेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें, जिससे आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

मकर राशि - शत्रुओं पर विजय दिलाने में मददगार साबित होगा। करियर में पुरानी मेहनत का फल मिलेगा और आपके विरोधी शांत रहेंगे। बिजनेस में लाभ की अच्छी स्थिति बनी रहेगी। लव लाइफ में साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे और आप दोनों एक-दूसरे की बातों को बेहतर समझेंगे। स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आप नई स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। कल का दिन कठिन कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए उपयुक्त है।

कुंभ राशि- आपके रचनात्मक विचारों की प्रशंसा होगी और आप अपने काम में निखार ला पाएंगे। बिजनेस में कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप सही योजना बनाएं। लव लाइफ में साथी के साथ हल्की-फुल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन प्रेम बना रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कल आपको अपने बच्चों की शिक्षा या भविष्य से जुड़ी किसी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है।

मीन राशि- घर-परिवार की समस्याओं के कारण कार्यस्थल पर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत आ सकती है। बिजनेस में सावधानी से काम लें और कोई बड़ा फैसला न लें। लव लाइफ में साथी के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा धैर्य की जरूरत होगी। स्वास्थ्य में माता-पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। कल व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करने से बचें और अपने काम पर ध्यान लगाएं।

शरीर के हिसाब से करें जींस का चयन

आज के फैशन ट्रेंड में जींस हर उम्र के लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन सही जींस चुनना हमेशा आसान नहीं होता। अक्सर लोग सिर्फ डिजाइन या ट्रेंड देखकर जींस खरीद लेते हैं, जो उनके शरीर के टाइप पर फिट नहीं बैठती और लुक खराब कर देती है। फैशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, हर व्यक्ति का बॉडी टाइप अलग होता है और उसी के हिसाब से जींस का चयन करना चाहिए। खासतौर पर महिलाओं को तो इसका खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सही फिटिंग की जींस न केवल आपके लुक को स्टाइलिश बनाती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। आजकल मार्केट में स्किनी, स्ट्रेट, बूटकट और रिलैक्स्ड फिट जैसी कई वैरायटी मौजूद हैं। अगर आप अपने बॉडी शेप को समझकर जींस चुनते हैं, तो आपका ओवरऑल लुक और भी आकर्षक दिखता है।

1. स्लिम बॉडी टाइप :- अगर आपका शरीर स्लिम है, तो आपको ऐसी जींस चुननी चाहिए जो आपके फिगर को थोड़ा डिफाइन और बैलेंस दिखाए। स्किनी फिट या स्लिम फिट जींस इस बॉडी टाइप पर काफी अच्छी लगती है क्योंकि यह पैरों को शेप देकर लुक को स्मार्ट बनाती है। हल्के स्ट्रेच वाली डेनिम भी बेहतर रहती है ताकि मूवमेंट आरामदायक रहे। बहुत ज्यादा ढीली जींस पहनने से लुक और पतला दिख सकता है, इसलिए फिटेड स्टाइल ज्यादा उपयुक्त माना जाता है।

2. कर्वी बॉडी टाइप :- कर्वी बॉडी टाइप के लिए ऐसी जींस चुननी चाहिए जो कमर और हिप्स को सही तरह से सपोर्ट दे। हाई-वेस्ट स्ट्रेट फिट या बूटकट जींस इस बॉडी शेप पर सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि यह शरीर के कर्व्स को बैलेंस करती है और एक स्मूथ सिल्हूट देती है। स्ट्रेच डेनिम वाली जींस पहनने से आराम भी मिलता है और फिटिंग भी बेहतर रहती है। बहुत टाइट स्किनी जींस से बचना चाहिए, क्योंकि इससे अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है।

3. एथलेटिक बॉडी टाइप :- एथलेटिक बॉडी में शरीर फिट और मस्कुलर होता है, इसलिए ऐसी जींस चुननी चाहिए जो बॉडी के साथ बैलेंस बनाए रखे। रिलैक्स्ड फिट या टेपर जींस इस बॉडी टाइप के लिए परफेक्ट रहती है। यह लुक को न तो बहुत टाइट बनाती है और न ही बहुत ढीला, जिससे एक स्मार्ट और क्लीन अपीयरेंस मिलता है। हल्के डार्क शेड्स की डेनिम भी इस बॉडी टाइप पर काफी अच्छी लगती है और स्टाइल को और बेहतर बनाती है।

4. रेक्टेंगल बॉडी टाइप :-इस बॉडी शेप में कमर कम डिफाइंड होती है और शरीर लगभग सीधा दिखता है। ऐसे में फ्लेयर्ड या हाई-वेस्ट जींस पहनने से कमर को शेप मिलता है और एक कर्वी इफेक्ट क्रिएट होता है। यह स्टाइल शरीर को ज्यादा बैलेंस्ड और स्टाइलिश दिखाता है। हल्की बेल बॉटम या वाइड लेग जींस भी इस बॉडी टाइप के लिए अच्छी रहती है क्योंकि यह लुक में डाइमेंशन जोड़ती है।

5. पियर शेप बॉडी :-पियर शेप बॉडी में हिप्स ज्यादा चौड़े होते हैं और अपर बॉडी पतली होती है। इस बॉडी टाइप के लिए स्ट्रेट या बूटकट जींस सबसे बेहतर विकल्प मानी जाती है क्योंकि यह शरीर को बैलेंस्ड लुक देती है। डार्क कलर की जींस हिप्स एरिया को स्लिम दिखाने में मदद करती है। बहुत ज्यादा टाइट फिट से बचना चाहिए और आरामदायक फिटिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि पूरा लुक एलिगेंट और स्टाइलिश लगे।

आपके बालों के लिए कौन-सा तेल सबसे बेस्ट

हेयर केयर एक्सपर्ट्स के अनुसार, आपके बालों का प्रकार ही तय करता है कि कौन सा तेल आपके लिए सबसे ज्यादा असरदार रहेगा। गलत तेल लगाने से कई बार बालों की समस्याएं कम होने की बजाय और बढ़ सकती हैं। इसलिए बालों की जरूरत को समझकर ही हेयर ऑयल चुनना चाहिए। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो उन्हें गहरी नमी की जरूरत होती है, जबकि ऑयली स्कैल्प वाले लोगों को ऐसा तेल चाहिए जो अतिरिक्त तेल और गंदगी को नियंत्रित करने में मदद करे। वहीं हेयर फॉल और समय से पहले सफेद होने वाले बालों के लिए ठंडक देने वाले और पोषण से भरपूर तेल अधिक फायदेमंद माने जाते हैं। सही तेल न केवल बालों को पोषण देता है बल्कि स्कैल्प को स्वस्थ बनाकर हेयर ग्रोथ को भी बेहतर कर सकता है।

ड्राई, फ्रिजी और रूखे बालों के लिए कौन सा तेल लगाएं?

अगर आपके बाल रूखे, बेजान और जल्दी टूटने वाले हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं, तिल का तेल, बादाम का तेल, अरंडी का तेल ये तेल बालों को गहराई से पोषण देने में मदद करते हैं। इनमें मौजूद फैटी एसिड और विटामिन बालों की नमी बनाए रखते हैं, जिससे ड्राइनेस और टूटने की समस्या कम हो सकती है।

हेयर फॉल, पतले बाल और समय से पहले सफेद होने की समस्या

अगर आप लगातार बाल झड़ने, बाल पतले होने या कम उम्र में सफेद बालों की समस्या से जूझ रहे हैं तो तीन तरह के तेल उपयोगी साबित हो सकते हैं। नारियल तेल, भृंगराज तेल, आंवला तेल ये तेल स्कैल्प को ठंडक पहुंचाने के साथ बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। नियमित मालिश से स्कैल्प में रक्त संचार बेहतर हो सकता है।

ऑयली स्कैल्प और डैंड्रफ वालों के लिए कौन सा तेल बेहतर?

ऑयली स्कैल्प वाले लोगों को अक्सर चिपचिपाहट, खुजली और डैंड्रफ की समस्या होती है। ऐसे में उपयोगी हो सकते हैं, सरसों का तेल,नीम का तेल,टी ट्री इन्फ्यूज्ड ऑयल, इन तेलों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो स्कैल्प को साफ रखने और अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।

हेयर ऑयल लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

बालों में जरूरत से ज्यादा तेल लगाने से बचें। हल्के हाथों से स्कैल्प मसाज करें। तेल को लंबे समय तक जमा न रहने दें। सप्ताह में 1 से 2 बार तेल लगाना अधिकांश लोगों के लिए पर्याप्त माना जाता है। साथ ही अपने स्कैल्प की स्थिति के अनुसार तेल का चुनाव करें।

जलजीरा पाउडर कैसे बनाएं?

गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडक पहुंचाने और पाचन को बेहतर बनाए रखने के लिए जलजीरा एक लोकप्रिय भारतीय पेय माना जाता है। बाजार में मिलने वाला जलजीरा स्वादिष्ट जरूर होता है, लेकिन इसे बार-बार खरीदना जेब पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में घर पर तैयार किया गया जलजीरा प्रीमिक्स न सिर्फ किफायती होता है बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर भी आपका पूरा नियंत्रण रहता है। खास बात यह है कि एक बार प्रीमिक्स बनाकर आप इसे कई हफ्तों तक स्टोर कर सकते हैं और जब मन करे, सिर्फ पानी मिलाकर ताजा जलजीरा तैयार कर सकते हैं।

बनाने के लिए सामग्री:

4 बड़े चम्मच भुना जीरा पाउडर, 2 बड़े चम्मच काला नमक,1 बड़ा चम्मच सादा नमक,2 बड़े चम्मच सूखा पुदीना पाउडर, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सूखा आमचूर पाउडर,1 छोटा चम्मच सौंठ पाउडर,1 छोटा चम्मच हींग।

बनाने की विधि:

सबसे पहले भुना जीरा, काला नमक, सादा नमक, सूखा पुदीना, काली मिर्च, आमचूर पाउडर, सोंठ और हींग को एक बड़े बाउल में डाल लें। अब सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं ताकि हर मसाला समान रूप से मिश्रित हो जाए। यदि आप हल्का मीठा स्वाद पसंद करते हैं, तो इसमें पिसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं। इसके बाद मिश्रण को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एक बार फिर बारीक पीस लें। तैयार प्रीमिक्स को छानकर एयरटाइट कांच या प्लास्टिक के कंटेनर में भर लें। कंटेनर को ठंडी और सूखी जगह पर रखें। इस तरह तैयार जलजीरा प्रीमिक्स लगभग 1 से 2 महीने तक ताजा बना रहता है और जब भी जरूरत हो, इसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है।

जलजीरा तैयार करने का तरीका:

जब भी ठंडा और स्वादिष्ट जलजीरा पीने का मन हो, एक गिलास ठंडा पानी लें और उसमें 1 से 2 चम्मच तैयार जलजीरा प्रीमिक्स डालें। चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह घोल लें ताकि मसाले पूरी तरह पानी में मिल जाएं। स्वाद बढ़ाने के लिए आधा नींबू निचोड़ें और कुछ बर्फ के टुकड़े डाल दें। यदि आप अधिक ताजगी चाहते हैं तो बारीक कटी पुदीने की पत्तियां भी मिला सकते हैं।

दुर्ग को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात : पं रविशंकर शुक्ल स्टेडियम का होगा कायाकल्प

जिला क्रीड़ांगन समिति ने दी सहमति

दुर्ग स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम बनेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम,जहां होंगी आधुनिक सुविधाएं। - फाइल: फोटो-नाहीद शेख

विशेष संवाददाता। दुर्ग। दुर्ग जिले में आधुनिक खेल सुविधाओं के विस्तार और अंतरराष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मंगलवार को जिला क्रीड़ांगन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पीडब्ल्यूडी सभाकक्ष में हुई इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और जिला क्रीड़ांगन समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर अभिजीत सिंह उपस्थित थे। बैठक के दौरान पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम के पुनर्विकास और खेल परिसंपत्तियों के बेहतर संचालन को लेकर कई बड़े प्रस्तावों पर सहमति बनी।

BCCI तैयार करेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम- बैठक में लिए गए सबसे बड़े फैसले के तहत दुर्ग के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अंतर्गत बैडमिंटन कोर्ट की जमीन को सुरक्षित रखते हुए, स्टेडियम की शेष बची हुई भूमि को छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के माध्यम से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को 33 वर्षों के लिए लीज पर सौंपा जाएगा। इस संबंध में अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्ताव जल्द ही राज्य शासन को भेजा जाएगा।

जर्जर भवनों का होगा अपलेखन- बैठक में स्टेडियम परिसर के भीतर स्थित पुराने और जर्जर हो चुके भवनों को तोड़कर हटाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इन अनुपयोगी ढांचों को हटाकर खेल परिसर की खाली भूमि का उपयोग खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाएं और नए ट्रेनिंग सेंटर्स विकसित करने के लिए किया जाएगा।

स्टेडियम परिसर में संचालित दुकानों के अनुबंधों की समीक्षा करते हुए समिति ने सुरक्षा एवं विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार एक माह का नोटिस जारी कर दुकानें खाली कराने का निर्णय लिया। साथ ही सुरक्षा निधि का समायोजन एवं भुगतान नियमानुसार किए जाने के निर्देश दिए गए। इस कार्य के लिए नगर निगम आयुक्त, एसडीएम दुर्ग एवं संबंधित अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि डीएमएफ मद से निर्मित बैडमिंटन कोर्ट का समुचित रखरखाव, संचालन, मरम्मत और खेल गतिविधियों के विस्तार के लिए इसे जिला क्रीड़ांगन समिति को हस्तांतरित किया जाएगा। वहीं प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए आवश्यक भूमि को अतिक्रमण एवं अवरोधों से मुक्त कराने के उद्देश्य से स्टेडियम परिसर और आसपास स्थित एसएलआरएम सेंटर, उद्यान, गुमटियों तथा अन्य अस्थायी एवं स्थायी संरचनाओं को नियमानुसार हटाने की कार्यवाही की जाएगी। जिला क्रीड़ांगन समिति के संचालन, लंबित वित्तीय मामलों एवं सुरक्षा निधियों के भुगतान पर भी बैठक में चर्चा हुई। समिति के कोषाध्यक्ष पद पर जिला कोषालय अधिकारी को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया, जिनके संयुक्त हस्ताक्षर से अध्यक्ष जिला क्रीड़ांगन समिति एवं कलेक्टर की स्वीकृति उपरांत भुगतान और वित्तीय निस्तारण की कार्यवाही की जाएगी।

दुर्ग के आनंद सरोवर में आध्यात्मिक समागम

हेमलता दीदी ने व्यावहारिक बातों पर अपना अमूल्य दिया उद्बोधन

मम्मा के पुण्य स्मृति मास पर विशेष आयोजन

दुर्ग। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के बघेरा स्थित ÷आनंद सरोवर÷ में एक भव्य आध्यात्मिक समागम का आयोजन किया गया। इस समागम में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय निर्देशिका राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी हेमलता दीदी का गरिमामयी शुभागमन हुआ। उनके पावन सानिध्य में उपस्थित सभी भाई-बहनों ने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के गुरुमंत्र सीखे। कार्यक्रम की शुरुआत में कुमारी तेजस्वी, प्रियांशी, युक्ति और चंद्राणी द्वारा एक बेहद सुंदर और भावपूर्ण स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया।अनुभव और तपस्या से मिली विशिष्ट पहचानब्रह्माकुमारी दुर्ग की संचालिका रीटा दीदी ने हेमलता दीदी का आत्मीय स्वागत करते हुए उनके कुशल नेतृत्व की सराहना की। रीटा दीदी ने कहा, ÷आपके कुशल निर्देशन में सभी सेवाकेंद्रों के भाई-बहनों को समय-समय पर अनुभव युक्त मार्गदर्शन मिलता रहता है। आपने अपनी कठिन तपस्या और कुशाग्र बुद्धि के बल पर इंदौर जोन (मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़) को देश भर के ब्रह्माकुमारीज सेवाकेन्द्रों में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है।÷मम्मा की स्मृति में आंतरिक तपस्या का महीनाउल्लेखनीय है कि जून महीने को प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की प्रथम मुख्य संचालिका ओम राधे (मातेश्वरी जी/मम्मा) के पुण्य स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पूरे मास में साधक अपनी विशेष आध्यात्मिक उन्नति के लिए आंतरिक तपस्या के भिन्न-भिन्न आयोजन करते हैं। इसी श्रृंखला के तहत आयोजित इस समागम में हेमलता दीदी ने उपस्थित भाई-बहनों को आध्यात्मिक पुरुषार्थ की छोटी-छोटी और व्यावहारिक बातों पर अपना अमूल्य उद्बोधन दिया।

भीषण गर्मी के बीच खुले स्कूल, प्रार्थना में छात्र बेहोश

जेआरडी स्कूल का मामला : अभिभावकों में भारी आक्रोश

दुर्ग। जिले में जारी भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच आज से स्कूल खुलने के पहले ही दिन एक बड़ा और चिंताजनक मामला सामने आया है। जेआरडी स्कूल में सुबह प्रार्थना सभा के दौरान एक छात्र तेज गर्मी के कारण अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो गया। छात्र के गिरते ही स्कूल परिसर में हड़कंप और अफ़रा-तफ़री का माहौल बन गया। आनन-फानन में स्कूल प्रबंधन ने छात्र को उठाया और तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई।अभिभावकों की चेतावनी को प्रबंधन ने किया नजरअंदाजइस घटना के बाद से स्कूल पहुंचे अभिभावकों में भारी नाराजगी और आक्रोश देखा जा रहा है। परिजनों का कहना है कि वे लगातार भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश (गर्मी की छुट्टियां) बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पालकों की मांग थी कि बच्चों को लू और बीमारी से बचाने के लिए स्कूल 1 जुलाई से खोले जाएं। इसके बावजूद प्रशासन और स्कूल प्रबंधन ने निर्धारित समय यानी 16 जून से ही स्कूलों का संचालन शुरू कर दिया, जिसका खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है।अधिकारियों ने साधी चुप्पी, स्थिति पर रखी जा रही नजरअभिभावकों ने सख्त लहजे में कहा है कि कड़कती धूप में छोटे बच्चों को स्कूल भेजना उनके स्वास्थ्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है। पालकों ने जिला प्रशासन से बच्चों की सुरक्षा और सेहत को प्राथमिकता देते हुए समय में बदलाव करने या छुट्टियां बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल, इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन और संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारी बैकफुट पर हैं और स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कह रहे हैं।

भिलाई में देर रात डकैती : मरौदा की बीआरपी कॉलोनी में 60 हजार की लूट

ठेका श्रमिक पर नकाबपोश बदमाशों ने किया जानलेवा हमला

भिलाईनगरः भिलाई के मरौदा स्थित बीआरपी कॉलोनी में रविवार देर रात अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक सूने घर में घुसकर दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने भिलाई इस्पात संयंत्र (सेल) के एक ठेका श्रमिक युवक के सिर पर भारी वस्तु से हमला कर उसे बेहोश कर दिया, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और घर में रखी नगदी सहित करीब 60 हजार रुपये के माल पर हाथ साफ कर फरार हो गए। इस सनसनीखेज घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है।

दीवार फांदकर अंदर पहुंचे पिता, बरामदे में बेहोश मिला बेटा- मिली जानकारी के अनुसार, बीआरपी कॉलोनी स्टेशन मरौदा निवासी एक श्रमिक अपने पुत्र रावेन्द्र सिंह के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी और बेटी करीब एक महीने से अपने गृह ग्राम बरहटा (कटनी, म.प्र.) गई हुई हैं। पिता जामुल के एसीसी प्लांट में काम करते हैं, जबकि बेटा रावेन्द्र बीएसपी में ठेका श्रमिक है। 14 जून की रात रावेन्द्र सेकंड शिफ्ट की ड्यूटी कर घर लौटा था, जिसके बाद रात करीब 10 बजे उसके पिता अपनी नाइट ड्यूटी पर चले गए। 15 जून की सुबह जब पिता घर लौटे, तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज लगाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने अनहोनी की आशंका में दीवार फांदकर भीतर प्रवेश किया। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए; बेटा रावेन्द्र बरामदे में लहूलुहान और बेहोश पड़ा था और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था।

आवाज सुनकर जागा था युवक, बदमाशों ने सिर पर किया वार- परिजनों ने आनन-फानन में रावेन्द्र को अस्पताल पहुंचाया। होश में आने पर पीड़ित ने बताया कि रात करीब 2 बजे घर में कुछ खटपट की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली थी। जब वह देखने गया, तो घर के अंदर 3 से 4 अज्ञात नकाबपोश बदमाश घुसे हुए थे। रावेन्द्र ने जब उनका विरोध करने की कोशिश की, तो बदमाशों ने उसके सिर पर किसी भारी चीज से जोरदार हमला कर दिया, जिससे वह वहीं गिरकर बेहोश हो गया। इसके बाद बदमाशों ने बेडरूम में रखी लोहे की पेटी का ताला तोड़ा और उसमें रखे चांदी का करधन, एक जोड़ी चांदी की पायल तथा ?30,000 नगद लेकर चंपत हो गए। पुलिस आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता : स्कूल शुरू होने से पहले स्कूल बस की जांच एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया

जशपुरनगर। डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा-निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पटनवार एवं उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) के.आर. चौहान के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस जशपुर, परिवहन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से रक्षित केंद्र जशपुर में स्कूल बस जांच एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया।आयोजित शिविर में जिले की 15 स्कूली बसों का व्यापक निरीक्षण किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्र-छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करना था। जांच के दौरान बसों के पंजीयन प्रमाण पत्र, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, रोड टैक्स एवं वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की बारीकी से जांच की गई। साथ ही वाहन चालकों एवं परिचालकों को यातायात नियमों एवं संकेतों की जानकारी देते हुए सुरक्षित वाहन संचालन, नशामुक्त रहकर वाहन चलाने तथा बच्चों को सुरक्षित तरीके से बस में चढ़ाने एवं उतारने के संबंध में आवश्यक समझाइश दी गई। वाहन परीक्षण के दौरान जिला परिवहन अधिकारी गिरीश चंद्र इंद्रवाल, यातायात प्रभारी उप निरीक्षक खेमराज ठाकुर व उनकी टीम के द्वारा दस्तावेजों की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा बस चालकों एवं परिचालकों का नेत्र परीक्षण, रक्तचाप (बीपी) एवं शुगर जांच भी की गई। इस दौरान जिला चिकित्सालय जशपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजू प्रसाद गुप्ता, नेत्र सहायक अधिकारी सविता मिश्रा, स्टाफनर्स ऐलिन रोस एक्का, वार्ड बॉय निरंजन नायक एवं सामाजिक कार्यकर्ता वृतिका मिश्रा उपस्थित रहे। पुलिस की वाहन शाखा के द्वारा स्कूली बसों के हेडलाइट, ब्रेक लाइट, स्टीयरिंग, टायर, क्लच, एक्सीलेटर, सीटों की स्थिति, हॉर्न एवं रिफ्लेक्टर सहित अन्य तकनीकी पहलुओं का निरीक्षण किया गया। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा नगर सेना जशपुर के जवानों द्वारा बसों में आग लगने जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव एवं सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस व परिवहन विभाग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट निर्धारित मानकों के अनुरूप बसों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर, आपातकालीन खिड़की, फर्स्ट एड किट, अग्निशमन यंत्र, स्कूल का नाम, टैलीफोन नंबर, चालक का मोबाइल नंबर एवं स्कूल बस की पहचान संबंधी चिन्हों की भी जांच की गई। मामले में डी आई जी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ लाल उमेद सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के विशेष जांच एवं जागरूकता अभियान लगातार संचालित किए जा रहे हैं, जिससे जिले में सुरक्षित एवं व्यवस्थित स्कूल परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

आज से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर 25 हजार तक जुर्माना

धमतरी। वर्षा ऋतु में मछलियों के वंश वृद्धि प्रजनन एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु क्लोज सीजन घोषित किया है। सहायक संचालक, मछलीपालन विभाग ने बताया कि छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम.1972 की धारा 3-2 के तहत लागू इस व्यवस्था के अनुसार धमतरी जिले के अधिकांश जल संसाधनों में इस अवधि के दौरान मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि जिले के सभी नदी, नाले, जलाशय तथा अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों में मछली पकड़ने पर रोक रहेगी। हालांकि ऐसे छोटे तालाब एवं जल स्रोत जिनका संबंध किसी नदी या नाले से नहीं है तथा जलाशयों में संचालित केज कल्चर गतिविधियां इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। सहायक संचालक ने यह भी बताया कि मानसून के दौरान मछलियों की वंश वृद्धि होती है, इसलिए इस अवधि में मत्स्याखेट पर रोक लगाना जलीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए आवश्यक है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन द्वितीय अधिनियम.2025 के तहत छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम.1948 की धारा 5 के अनुसार 25 हजार रुपये तक के शास्ति से दण्डित किए जाने का प्रावधान है। यह नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जलस्त्रोत, जिनका संबंध किसी नदी, नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किए जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे।

भिलाई में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ निगम की कार्रवाई

फल ठेलों और दुकानों से वसूला जुर्माना

शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का अभियान तेज

भिलाईनगर। शहर को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है।

इसी सिलसिले में निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के कड़े निर्देश पर जोन-1 के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वार्ड क्रमांक 10, लक्ष्मी नगर क्षेत्र में एक विशेष औचक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने फल-सब्जी ठेलों और कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की।लाइसेंस की भी हुई जांच, कई दुकानों पर जुर्माना लगाया.अभियान के दौरान अधिकारियों ने न केवल प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की जब्ती की, बल्कि दुकानों के अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) की भी सघन जांच की।निरीक्षण के दौरान कुल 15 ठेलों और दुकानों में नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर नगर निगम की टीम ने तत्काल चालानी कार्रवाई की। कई फल ठेलों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर 50 से 100 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया। नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 11 फल और सब्जी ठेलों का चालान काटा गया। बिना लाइसेंस चल रही दुकानों पर बड़ी कार्रवाईनिगम की इस कार्रवाई के दौरान एक जूता दुकान और एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं पाया गया। इस गंभीर नियम उल्लंघन के लिए दोनों दुकानों पर 500-500 रुपये का भारी जुर्माना ठोका गया। इस पूरी कार्रवाई के तहत सोनू चौहान, किशन, राहुल सोनकर, विक्की, छोटू सोनकर, सुजीत, सुनील, जोगिंदर, उमेश साह, लगन देवी, अजय और गणेश सहित अन्य व्यापारियों पर चालान बनाया गया। टीम ने मौके पर कुल 2,120 रुपये की जुर्माना राशि वसूली। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए यह विशेष अभियान आगे भी बिना रुके लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हरा-भरा बनाने में सहयोग देने की अपील की है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। डाक पंजीयन क्रमांक- सीजी/दुर्ग/लोकतंत्र प्रहरी/2026-28, Email : loktantraprahrinews@gmail.com